RNI NO.- CHHHIN/2023/87391

स्वतंत्र छत्तीसगढ़

अंक-05 | वर्ष-4 | माह-सितम्बर 2025 | प्रकाशन तिथि- सितम्बर2025 | रायपुर से प्रकाशित | पृष्ठ-40 | मूल्य-11/-

छत्तीसगढ़ ऊर्जा क्षेत्र की नई पहचान बनेगा नवा रायपुर का संयुक्त मुख्यालय भवन...

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना महंगे बिजली बिल की चिंता खत्म...

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

भारतीय सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम
की संयुक्त विशेष भर्ती योजना

"बीमा सखी"

महिला बीमा अभिकर्ता

3 वर्ष तक प्रतिमाह मानदेय

- 1st Year Rs. 7000 P.M.
- 2nd Year Rs. 6000 P.M.
- 3rd Year Rs. 5000 P.M.

साथ ही आकर्षक
अतिरिक्त कमीशन

बीमा सखी के अन्य लाभ

पार्ट टाईम/फूल टाइम कार्य
ग्रुप बीमा, होम लोन इत्यादि

आवश्यक शर्तें : 10 वीं पास उम्र 18 वर्ष से अधिक

एलआईसी
महिला विशेष भर्ती

महिला कैरियर एजेंट के रूप में
एलआईसी से जुड़ें

Years	RS
1st	Rs. 7000/-
2nd	Rs. 6000/-
3rd	Rs. 5000/-

B.V.S.Rajkumar
(OVER FOUR DECADES OF EXPERIENCE)
L.I.C.OF INDIA, RAIPUR

अधिक जानकारी
के लिए सम्पर्क करें

98266-38002

स्वतंत्र छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ से प्रकाशित एक सम्पूर्ण पत्रिका

प्रधान संपादकः

जी. भूषण राव

समाचार संपादकः

जी.वी.एस. रूक्मणि देवी

उप संपादकः

राखी श्रीवास्तव

सलाहकार संपादकः

रविश बेंजामिन

अशोक तोमर

मार्केटिंग हेडः

शैलेन्द्र दवे

मार्केटिंग प्रतिनिधिः

हरिमोहन तिवारी

आवरण सज्जाः

Infinity

ब्यूरो हेडः

बिलासपुरः विनीत चौहान

जशपुरः आनंद गुप्ता

कोरियाः प्रवीण निशी

बस्तरः सुनील सिंह राठौर

आफिसः

बी-13, बसंत पार्क

अनमोल सुपर मार्केट के पास

महावीर नगर, न्यू पुरेना रायपुर छ.ग.

ईमेलः swatantrachhattisgarh@gmail.com

वेबसाईटः www.swatantrachhattisgarh.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

जी. भूषण राव द्वारा सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती रायपुर द्वारा मुद्रित एवं बी-13, बसंत पार्क, अनमोल सुपर मार्केट के पास, महावीर नगर, न्यू पुरेना, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित

मो.:- 99934-54909

संपादकः जी. भूषण राव

पत्रिका में प्रकाशित लेख, लेखकों के अपने विचार है, किसी भी विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्र रायपुर होगा।

वार्षिक सदस्यता शुल्क सभी

(विशेषांकों सहित प्रस्तावित) 132/-रू.मात्र

Pg 3

गांव-गरीब-किसान के उत्थान का संकल्प-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का कबीरधाम प्रवास

Pg 8

धमतरी से गूंजेगी स्वच्छ आतिशबाज़ी-महिला सशक्ति करण और पर्यावरण संरक्षण की अनोखी मिसाल...

Pg 12

बेबीलॉन टावर अग्नि दुर्घटना-जांबाज़ युवाओं ने बचाई अनगिनत जानें ...

Pg 18

आयुष्मान योजना में पारदर्शिता और सुधार की राह पर छत्तीसगढ़...

Pg 28

कुछ चटपटा खाने का कर रहा है मन ? तो घर पर बनाएं स्ट्रीट स्टाइल कटोरी चाट...

इतिहास से सबक और आज की विदेश नीति

इतिहास अक्सर हमें वर्तमान की चुनौतियों को समझने का रास्ता दिखाता है। 1950 के दशक में अमेरिका ने भारत को उसकी अंतरराष्ट्रीय हैसियत समझाने की कोशिश की थी, और आज 2025 में भी हम वैसा ही परिदृश्य देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का हालिया रवैया–भारत पर टैरिफ थोपना और पाकिस्तान की ओर झुकाव दिखाना–अमेरिकी विदेश नीति की उस परंपरा को दोहराता है, जिसे भारत दशकों पहले झेल चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टोक्यो ट्रायल में भारतीय न्यायाधीश राधाबिनोद पाल का स्वतंत्र मत ऐतिहासिक था। उन्होंने सभी जापानी प्रतिवादियों को कानूनी आधार पर बरी कर दिया। यह अमेरिका के लिए अप्रत्याशित नहीं बल्कि उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि वह जापान में अमेरिकी शैली का लोकतंत्र स्थापित करना चाहता था और इस असहमति ने मुकदमे की निष्पक्षता को विश्वसनीयता दी।

भारत सरकार शुरू में इस मत से असहज थी। नेहरू ने आलोचना भी की, लेकिन बाद में समझा कि इससे जापान में भारत की दृश्यता और सद्भावना बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप, भारतीय राजनयिकों ने इसका संतुलित उपयोग किया। 1950 के दशक में अमेरिका ने जापान को साम्यवाद विरोधी गढ़ बनाने की रणनीति अपनाई। सैन फ्रांसिस्को संधि (1951-52) के माध्यम से उसने एशिया में अपने सैन्य ठिकाने सुनिश्चित किए। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि उसका मानना था कि एशिया का भविष्य किसी बाहरी ताकत द्वारा निर्धारित नहीं होना चाहिए।

बाद में जब जापान ने 'क्लास-ए' युद्ध अपराधियों की रिहाई पर भारत से सहमति मांगी, तो भारत ने पाल के मत के अनुरूप हामी भर दी। लेकिन अमेरिका ने भारत को यह कहकर अलग कर दिया कि उसने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए उसकी राय अप्रासंगिक है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को मताधिकार दिलाने की कोशिश कर भारत को और उकसाया गया। यह स्पष्ट संदेश था कि अमेरिका भारत को उसके स्थान का एहसास कराना चाहता है। आज 2025 में, भारत पर टैरिफ लगाने और पाकिस्तान की ओर झुकाव दिखाने की ट्रम्प की नीति उसी ऐतिहासिक पटकथा का नया संस्करण है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी विदेश नीति अपने रणनीतिक हितों के आगे मित्रता या लोकतंत्र के सिद्धांतों को पीछे रख देती है। भारत के लिए सबक साफ है–अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत और स्वायत्तता कायम रखना उतना ही ज़रूरी है जितना व्यावहारिक कूटनीति। हमें अमेरिकी दबाव या पाकिस्तान-प्रेम से विचलित नहीं होना चाहिए। बल्कि, इतिहास की तरह, हमें यह दिखाना चाहिए कि भारत किसी भी शक्ति के इशारों पर नहीं चलता।टोक्यो ट्रायल से लेकर ट्रम्प के टैरिफ तक, भारत ने अमेरिका की एक जैसी रणनीतियाँ देखी हैं। फर्क सिर्फ समय का है। हमें अपनी विदेश नीति को इतिहास से मिले इन सबकों के आधार पर और अधिक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी बनाना होगा। यही रास्ता भारत को दुनिया में उसकी वास्तविक हैसियत दिलाएगा।

(ये मेरे अपने विचार हैं)

आपका अपना

भूषण राव

गांव-गरीब-किसान के उत्थान का संकल्प-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का कबीरधाम प्रवास

छत्तीसगढ़ की धरती हमेशा से ग्राम्य संस्कृति, कृषि और सामाजिक समरसता की प्रतीक रही है। यहां की मिट्टी की खुशबू, यहां के किसानों की मेहनत और ग्रामीण अंचलों की आत्मीयता पूरे प्रदेश की पहचान है। यही कारण है कि वर्तमान राज्य सरकार गांव, गरीब, किसान और युवा वर्ग को विकास की धुरी मानकर कार्य कर रही है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का हाल ही में कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम विचारपुर और भिभौरी प्रवास इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ने सीधे ग्रामीणों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों से संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं, मांगों व सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की हर योजना और नीति का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुँचना चाहिए। यही शासन का मूल उद्देश्य है और यही सरकार की प्राथमिकता भी।

विकास कार्यों का लोकार्पण और नई पहलें

ग्राम विचारपुर में इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। इनमें 10 लाख रुपये की लागत से झोंका नाला में पुलिया निर्माण, 5 लाख रुपये की लागत से मंच निर्माण और 3 लाख रुपये की लागत से ज्योति कक्ष निर्माण प्रमुख हैं। ये कार्य न केवल गांव के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेंगे बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेंगे।

इसके अतिरिक्त, ग्राम विचारपुर के विकास के लिए कुल 82 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से अनेक कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष कार्य तेजी से प्रगति पर हैं। यह निवेश सिर्फ वर्तमान सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए नहीं है बल्कि आने वाले समय में गांव के भविष्य को नई दिशा देने का एक ठोस प्रयास है।

शासन-प्रशासन की पहुंच हर गांव तक

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि शासन-प्रशासन तक पहुँचने में किसी भी नागरिक को कठिनाई नहीं होगी। प्रत्येक समस्या का निराकरण प्राथमिकता से किया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि समाधान स्थल पर ही सुनिश्चित हो। उनका यह संदेश ग्रामीणों के लिए आत्मविश्वास और भरोसा जगाने वाला है।

उन्होंने साफ शब्दों में कहा - आपकी समस्या ही मेरी समस्या है और उसका समाधान करना ही मेरा दायित्व है। यह कथन शासन के सेवा-भाव और जनसमर्पण की झलक देता है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर जोर

प्रदेश सरकार के विकास दृष्टिकोण में शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। श्री शर्मा ने कहा कि बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना आवश्यक है ताकि वे भविष्य में प्रदेश और देश की प्रगति में योगदान कर सकें। उन्होंने ग्रामीण अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें।

स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी सरकार लगातार निवेश कर रही है। गांव-गांव में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाना और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान सरकार की प्राथमिकता में है।

इसी प्रकार सड़क, बिजली, सिंचाई और पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध कार्य किए जा रहे हैं। श्री शर्मा ने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में प्रदेश का कोई भी गांव इन बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं

रहेगा।

किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

किसान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य किसानों को सशक्त बनाना है। किसानों की आय में वृद्धि, फसलों के लिए समय पर समर्थन मूल्य, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार और उन्नत बीज व तकनीक की उपलब्धता इसी दिशा में किए जा रहे प्रयास हैं।

कृषि के साथ-साथ पशुपालन, बागवानी और वनोपज आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और किसानों की निर्भरता केवल परंपरागत खेती पर नहीं रहेगी।

युवा और महिलाएं -आत्मनिर्भरता की ओर

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और खेलकूद में आगे बढ़कर अपनी ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार की योजनाओं में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार दोनों के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महिलाओं की आत्मनिर्भरता भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। स्वयं सहायता समूहों, लघु उद्योगों और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उपमुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी और भी व्यापक होगी और वे सामाजिक-आर्थिक जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी।

सरकार की नीतियों का व्यापक प्रभाव

विजय शर्मा ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि सरकार की हर नीति का मकसद नागरिकों का जीवन आसान, सुरक्षित और समृद्ध बनाना है। चाहे वह किसान हो, महिला हो, युवा हो या कोई बुजुर्ग—हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार तभी सफल होगी जब नागरिक भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है।

सामाजिक चेतना और नई राह

यह भी उल्लेखनीय है कि उपमुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सिर्फ योजनाओं का लाभ लेने की अपील नहीं की बल्कि सामाजिक चेतना जगाने का भी संदेश दिया। उन्होंने युवाओं से कहा कि नशे से दूर रहें और खेलकूद व शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। यह संदेश सिर्फ एक अपील नहीं बल्कि सामाजिक जीवन को स्वस्थ और प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है।

विकास की नई मिसाल बनने की ओर

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री के वक्तव्य ने साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता गांव-गरीब-किसान का उत्थान है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि रोजगार के अवसरों में भी इजाफा होगा। महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर नए कदम बढ़ाएंगी और हर गांव विकास की नई मिसाल बनेगा।

यह विजन केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। ग्राम विचारपुर में किए गए विकास कार्य और 82 लाख रुपये की स्वीकृति इसका ठोस प्रमाण हैं।

छत्तीसगढ़ का विकास तभी संभव है जब गांवों की तस्वीर बदलेगी। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का कबीरधाम प्रवास इस बात का प्रतीक है कि सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुन रही है, समाधान कर रही है और नए विकास कार्यों का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा—ये पांचों वर्ग छत्तीसगढ़ की प्रगति के आधार स्तंभ हैं। सरकार ने इन्हें केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई हैं और इन्हीं के दम पर नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण की परिकल्पना की जा रही है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विजय शर्मा का यह संदेश कि आपकी समस्या ही मेरी समस्या है सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि एक जनसेवा का संकल्प है। इस संकल्प के साथ अगर योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी और पारदर्शिता से होता है तो निश्चित ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के गांव विकास की ऐसी मिसाल बनेंगे जिन्हें पूरे देश में उदाहरण के रूप में देखा जाएगा।

छत्तीसगढ़ ऊर्जा क्षेत्र की नई पहचान बनेगा नवा रायपुर का संयुक्त मुख्यालय भवन...

छत्तीसगढ़ अपनी रजत जयंती वर्षगांठ मना रहा है और इसी ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर सेक्टर-24 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के संयुक्त मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया। गणेशोत्सव के पावन पर्व पर आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा-अर्चना कर भवन का थ्री-डी मॉडल अनावृत किया। उन्होंने इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत मौलश्री का पौधरोपण भी किया।

छत्तीसगढ़ की ऊर्जा यात्रा - 1400 मेगावाट से 30,000 मेगावाट तक

मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य की 25 वर्षीय यात्रा यह प्रमाण है कि जब संकल्प और संवेदनशीलता साथ चलते हैं तो परिणाम ऐतिहासिक होते हैं। वर्ष 2000 में जहाँ छत्तीसगढ़ की बिजली उत्पादन क्षमता केवल 1400 मेगावाट थी, वहीं आज यह क्षमता बढ़कर 30 हजार मेगावाट हो चुकी है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1320 मेगावाट क्षमता वाले नए संयंत्र का शुभारंभ इस उपलब्धि को और सुदृढ़ करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि यह प्रगति हर नागरिक के विश्वास, मेहनत और भागीदारी का परिणाम है। छत्तीसगढ़ अब न केवल अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

वैश्विक दृष्टिकोण और नई संभावनाएँ

मुख्यमंत्री ने जापान और दक्षिण कोरिया की अपनी हालिया यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब वैश्विक स्तर की अधोसंरचना और कार्यसंस्कृति की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि संयुक्त मुख्यालय भवन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा और यह ऊर्जा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भवन का निर्माण गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए।

तीन लाख करोड़ के एमओयू और उज्ज्वल भविष्य

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की नई उद्योग नीति के तहत हाल ही में पावर सेक्टर में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं। इससे आने वाले वर्षों में 30 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन संभव होगा। यह उपलब्धि न केवल प्रदेशवासियों को 24 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएगी, बल्कि पड़ोसी राज्यों की ज़रूरतों को भी पूरा करेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से छत्तीसगढ़ मुफ्त बिजली की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब इस योजना का लाभ दूरस्थ अंचलों तक पहुँच रहा है।

ग्रीन एनर्जी से सजेगा आधुनिक भवन

वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी को राज्य निर्माण में उनके योगदान के लिए नमन किया। उन्होंने कहा कि लगभग 270 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह भवन ग्रीन एनर्जी पर आधारित होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत सिद्ध होगा।

संयुक्त मुख्यालय भवन 10,017 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नौ मंजिला स्वरूप में निर्मित होगा। इसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए तीन अलग-अलग टॉवर होंगे।

यह भवन 1300 कर्मचारियों की कार्य क्षमता से युक्त होगा। इसमें

210 सीटों का आधुनिक प्रेक्षागृह, कर्मचारियों के लिए जिम, दो मंजिला बेसमेंट पार्किंग, मैकेनिकल स्टैक पार्किंग और ई-व्हीकल चार्जिंग की अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। भवन का निर्माण बीईई की पाँच सितारा और गृहा की फाइव स्टार ग्रीन रेटिंग मानकों के अनुरूप किया जा रहा है तथा भवन प्रबंधन प्रणाली से इसका संपूर्ण संचालन होगा।

ऊर्जा क्षेत्र में नया मील का पत्थर

नवा रायपुर में मंत्रालय, संचालनालय और पुलिस मुख्यालय के समीप स्थित यह भवन अंतर्विभागीय समन्वय को और सुदृढ़ करेगा तथा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊँचाई प्रदान करेगा। यह भवन न केवल कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि नए छत्तीसगढ़ की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बनेगा।

SEBI Rules: सेबी ने IPO के नियम हुवे नर्म, स्टार्टअप फाउंडर्स को मिलेगी बड़ी राहत

सेबी (SEBI) ने IPO नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए स्टार्टअप कंपनियों के फाउंडर्स और प्रमोटर्स को बड़ी राहत दी है। अब स्टार्टअप्स के प्रमोटर्स अपने पुराने ESOPs को बनाए रख सकेंगे। इस फैसले से रेजरपे, ग्रो, मीशो जैसे कई स्टार्टअप्स को फायदा मिलने की संभावना है। नए नियमों के तहत, यदि किसी कर्मचारी या फाउंडर को ESOP, SAR (स्टॉक एप्रीसिएशन राइट्स) या किसी अन्य तरह का बेनिफिट IPO के दस्तावेज दाखिल करने से कम से कम एक साल पहले मिला है, तो वह उसे आगे भी होल्ड कर सकता है। पहले की व्यवस्था में कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले प्रमोटर्स को अपने ESOP छोड़ने पड़ते थे।

मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि सेबी का यह कदम स्टार्टअप्स के लिए शेयर बाजार में उतरने का रास्ता आसान करेगा। साथ ही निवेशकों के विश्वास में भी बढ़ोतरी होगी।

इसके अलावा, सेबी ने इक्विटी और डेरिवेटिव्स सेगमेंट के सेटलमेंट शेड्यूल में भी बदलाव किया है। गणेश चतुर्थी और ईद-ए-मिलाद की वजह से 5 और 8 सितंबर को घोषित सेटलमेंट हॉलिडे के चलते उन दिनों के ट्रेड्स का निपटान आगे खिसकाया गया है। सेबी का कहना है कि इस कदम से मार्केट की स्थिरता बनी रहेगी और निवेशकों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।

छोटे लोन अब सीधे UPI से, RBI ने जारी किए नए दिशा-निर्देश...

छोटे-छोटे लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिनके तहत अब ग्राहक सीधे PI ऐप्स के माध्यम से छोटी क्रेडिट लाइन का लाभ उठा सकेंगे। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिनके पास बैंक खाता नहीं है या फिर बैंक शाखा तक पहुँचना मुश्किल है। फिनटेक सेक्टर से जुड़े जानकारों के अनुसार, बैंकों की योजना है कि छोटे लोन अब सीधे PI प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध कराए जाएँ। इसके लिए PHONEPE, PAYTM, BHARATPE और NAVI जैसे ऐप्स का उपयोग किया जाएगा। ICICI बैंक और KARNATAKA बैंक सहित कई बड़े व छोटे बैंक इस व्यवस्था को अपनाने की तैयारी में हैं। ग्राहक का क्रेडिट अकाउंट सीधे PI ऐप से लिंक होगा, जिससे गोल्ड लोन, एफडी के खिलाफ लोन, कंज्यूमर लोन और पर्सनल लोन जैसे उत्पाद तुरंत उपलब्ध हो सकेंगे।

बैंकों ने इस नए उत्पाद को लेकर RBI से ब्याज-मुक्त अवधि, बकाया राशि की रिपोर्टिंग और क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी भेजने जैसी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए थे। अब RBI ने सभी बिंदुओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद इसका परीक्षण शुरू हो गया है और धीरे-धीरे इसे ग्राहकों तक पहुँचाया जाएगा।

UPI प्लेटफ़ॉर्म का संचालन करने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने सितंबर 2023 में प्री-सैंक्शन क्रेडिट लाइन की सुविधा शुरू की थी। लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण बैंक इसे लागू नहीं कर पा रहे थे। हाल ही में NPCI ने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि क्रेडिट का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा, जिसके लिए वह मंजूर हुआ है।

वर्तमान में UPI के करीब 30 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 15 से 20 करोड़ सक्रिय हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुविधा से PI का इस्तेमाल और तेज़ी से बढ़ेगा। फिनटेक कंपनी ZETA का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक PI पर लेन-देन 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है।

हालाँकि, इसके साथ जोखिम भी जुड़े हैं। बैंक अधिकारियों का कहना है कि यदि इसे सावधानी से लागू नहीं किया गया, तो छोटे-छोटे लोन की वसूली चुनौतीपूर्ण होगी और डिफॉल्ट्स बढ़ सकते हैं। ऐसे में बैंकों को निगरानी और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम न केवल ग्राहकों को तेज़ और आसान लोन उपलब्ध कराएगा, बल्कि भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को भी नई मजबूती और रफ्तार देगा।

धमतरी से गूंजेगी स्वच्छ आतिशबाज़ी- महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की अनोखी मिसाल...

इस बार दिवाली की जगमगाहट में पर्यावरण की चिंता भी शामिल होगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से देशभर में ऐसी ग्रीन आतिशबाज़ी गूंजेगी, जो प्रदूषण रहित और पूरी तरह सुरक्षित होगी। खास बात यह है कि इन पर्यावरण अनुकूल पटाखों के निर्माण में 100 से अधिक ग्रामीण महिलाएँ जुटी हैं। यह पहल न केवल स्वच्छ और सुरक्षित त्योहार की ओर कदम है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी बन रही है।

ग्रीन आतिशबाज़ी से स्वच्छ पर्व की ओर

धमतरी के ग्राम चटोद में स्थापित श्री गणेशा फायरवर्क्स यूनिट में महिलाएँ पारंपरिक पटाखों की जगह ग्रीन पटाखों का निर्माण कर रही हैं। यहाँ तैयार पटाखों में बारूद का प्रयोग नहीं होता, जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और प्रदूषण भी न्यूनतम होता है। दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से लेकर विवाह समारोहों व अन्य आयोजनों के लिए भी इन ग्रीन आतिशबाज़ियों की विभिन्न किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रशासन की पहल और सुरक्षा इंतज़ाम

धमतरी कलेक्टर ने हाल ही में इस यूनिट का निरीक्षण किया और महिलाओं से सीधे संवाद किया। उन्होंने ग्रीन पटाखों की उत्पादन प्रक्रिया व गुणवत्ता की जानकारी लेने के साथ मौके पर पटाखा चलाकर उसकी सुरक्षा का अनुभव भी किया।

यूनिट को पाँच एकड़ भूमि लीज पर दी गई है। कलेक्टर ने प्रबंधन को निर्देश दिए कि—

- परिसर में अग्नि शमन की ठोस व्यवस्था रहे,
- नियमित रूप से मॉक ड्रिल कराई जाए,
- और ज्वलनशील पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध हो।
- उन्होंने कहा कि चटोद में स्थापित यह यूनिट 'लोकल से वोकल' और महिला सशक्तिकरण की प्रेरक मिसाल है।

महिलाओं के हाथों आत्मनिर्भरता

इस यूनिट में आज लगभग 100 से अधिक महिलाएँ कार्यरत हैं। उन्हें स्थायी रोजगार मिला है, जिससे उनके परिवार की आजीविका सुरक्षित हुई है। ग्रीन आतिशबाज़ी बनाकर ये महिलाएँ न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने में योगदान दे रही हैं।

ग्रीन पटाखों की खासियत

यूनिट के सेल्स हेड श्री आशीष सिंह बताते हैं कि ग्रीन पटाखे पूरी तरह सुरक्षित हैं। इनमें न बारूद का इस्तेमाल होता है और न ही हानिकारक धुआँ निकलता है। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बिना चिंता के त्योहार मना सकते हैं।

स्वच्छ दिवाली की ओर बढ़ता कदम

धमतरी की यह पहल पूरे प्रदेश और देश के लिए प्रेरणा है। यह सिर्फ ग्रीन आतिशबाज़ी नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है कि रोजगार, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण एक साथ संभव हैं। आने वाले समय में जब हर घर में सुरक्षित और प्रदूषण-मुक्त दिवाली मनाई जाएगी, तो उसमें धमतरी की महिलाओं की मेहनत और जज़्बे की झलक ज़रूर दिखेगी।

धमतरी की यह पहल दिखाती है कि अगर सही दिशा और सहयोग मिले तो गाँव की महिलाएँ भी बड़े बदलाव की वाहक बन सकती हैं। ग्रीन आतिशबाज़ी सिर्फ त्योहार की रोशनी नहीं, बल्कि पर्यावरण, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की नई उम्मीद है।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना- महंगे बिजली बिल की चिंता खत्म...

पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए एक प्रभावी एवं लाभकारी योजना साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिको को न केवल सस्ती और सतत् बिजली मिल रही है, बल्कि लोग बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

योजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करते हुए घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कराना है, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। सक्ति जिले के ग्राम दतौद निवासी श्री प्रभुदयाल चंद्रा ने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित कराया गया है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा श्री चंद्रा को 78 हजार रुपये की अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की गई है। इस समन्वित सहयोग से नागरिकों पर वित्तीय भार में उल्लेखनीय कमी आई है तथा सौर ऊर्जा को अपनाने हेतु प्रोत्साहन मिला है। श्री चंद्रा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा के माध्यम से न केवल बिजली की बचत हो रही है, बल्कि यह योजना हर परिवार को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है।

आने वाले समय में प्रदेश के प्रत्येक घर की छत पर यह सौर पैनल दिखाई देगा, जिससे महंगे बिजली बिल की चिंता समाप्त हो जाएगी। शासन की इस पहल से प्रदेश में हर वर्ग के नागरिक को सस्ती, सुलभ और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो रही है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन कायम रखने में भी सहयोग मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने हेतु तकनीकी मार्गदर्शन, विभागीय सहायता और वित्तीय अनुदान की व्यवस्था की गई है। इससे न केवल विद्युत खपत में कमी आई है, बल्कि उपभोक्ताओं की आय में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि भी हो रही है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन)

प्रधानमंत्री जनमन योजना के बारे में

लॉन्च- पीएम जनमन को 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ।

यह पहल भारत के 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री-पीवीटीजी विकास मिशन को आगे बढ़ाती है।

उद्देश्य- इस योजना का उद्देश्य व्यापक विकास हस्तक्षेप प्रदान करके विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।

लाभार्थी- इस योजना का लक्ष्य 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) के 75 पीवीटीजी समुदायों को लाभार्थी बनाना है।

नोडल मंत्रालय- जनजातीय कार्य मंत्रालय, 9-लाइन मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है ।

बजटीय परिव्यय- इस योजना के लिए कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये है , जिसमें केंद्रीय हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपये है ।

कवरेज अवधि- योजना की कवरेज अवधि 2023-24 से 2025-26 तक है ।

फोकस क्षेत्र- यह योजना पीवीटीजी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवास, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण, आजीविका और विद्युतीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करती है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के अन्य प्रमुख विवरण क्या हैं?

प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत हस्तक्षेप

मंत्रालय	गतिविधि	योजना
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकानों का प्रावधान	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
	सड़कों को जोड़ना	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप द्वारा जल आपूर्ति	जल जीवन मिशन (जेजेएम)
	सामुदायिक जल आपूर्ति	20 से कम परिवार (॥॥) की आबादी वाले गाँव/बस्तियाँ
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	दवा की लागत के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	समग्र शिक्षा
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और संचालन	आंगनवाड़ी सेवाएं
जनजातीय कार्य मंत्रालय	वन धन विकास केन्द्रों की स्थापना	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन
	बहुउद्देशीय केंद्रों(एमपीसी)का निर्माण	पीवीटीजी का विकास
विद्युत मंत्रालय	अविद्युतीकृत एचएच का विद्युतीकरण	पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)
गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	सड़कों और एमपीसी में सौर प्रकाश व्यवस्था	नई सौर ऊर्जा योजना
	0.3 किलोवाट सौर ऑफ-ग्रिड प्रणाली का प्रावधान	नई सौर ऊर्जा योजना
दूरसंचार विभाग	मोबाइल टावरों की स्थापना	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF)
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	व्यावसायिक शिक्षा और कौशल	समग्र शिक्षा अभियान और पीएम कौशल विकास

नई सौर ऊर्जा योजना

उद्देश्य- इसका उद्देश्य नवीकरणीय सौर ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके उन पीवीटीजी क्षेत्रों में विद्युतीकरण प्रदान करना है जहां ग्रिड बिजली संभव नहीं है।

अवयव

सौर गृह प्रकाश व्यवस्था (एसएचएलएस)- पीवीटीजी क्षेत्रों में बिखरे हुए गैर-विद्युतीकृत घरों में एस एच एल एस को आवश्यक उपकरणों और 5 साल के रखरखाव के साथ नि:शुल्क स्थापित किया जाएगा ।

सौर मिनी ग्रिड

पीवीटीजी क्षेत्रों में क्लस्टर किए गए घरों के लिए सौर मिनी ग्रिड स्थापित किए जाएंगे, जो प्रति घर 50,000 रुपये की सीएफए सहायता के साथ एलईडी बल्ब और पंखे जैसे उपकरण प्रदान करेंगे।

बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) का सौरीकरण

ग्रिड पहुंच के बिना एमपीसी पर ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा पैक स्थापित किए जाएंगे, जिसमें संपूर्ण प्रणाली लागत को कवर करने के लिए प्रति केंद्र 1 लाख रुपये का सीएफए समर्थन दिया जाएगा।

बजट- इस पहल के लिए कुल बजट 515 करोड़ रुपये है , जिसमें एसएचएलएस, सौर मिनी ग्रिड की स्थापना और पीवीटीजी क्षेत्रों में एमपीसी का सौरीकरण शामिल होगा।

नवीनतम अपडेट

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी बहुल क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आईईसी अभियान (अगस्त-सितंबर 2024 में) शुरू किया ।

इस अभियान का उद्देश्य भारत के 194 जिलों की 28,700 बस्तियों में 44.6 लाख व्यक्तियों (10.7 लाख परिवारों) तक पहुंचना था।

अभियान का प्राथमिक लक्ष्य सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दूरी और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियों का समाधान करना और यह सुनिश्चित करना है कि पीवीटीजी परिवारों को आधार कार्ड , जाति प्रमाण पत्र और जन धन बैंक खाते जैसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हों ।

बुनियादी ढांचे का विकास

कुल 226,064 पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे (19,788 पूरे हो चुके हैं), स्वास्थ्य सेवा के लिए 578 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) तैनात किए जाएंगे, 290,676 नल जल कनेक्शन स्थापित किए जाएंगे, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 2,746.17 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी और 123,530 गैर-विद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।

सौर ऊर्जा- नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत 5,067 घरों को विद्युतीकरण हेतु मंजूरी दी गई है।

बेबीलॉन टावर अग्नि दुर्घटना- जांबाज़ युवाओं ने बचाई अनगिनत जानें ...

राजधानी के बेबीलॉन टावर में बीती रात लगी भीषण आग ने पलभर में पूरे शहर को दहशत में डाल दिया। स्थिति भयावह थी, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस, दमकल कर्मियों और कुछ साहसी युवाओं की सूझबूझ और अदम्य साहस ने वह कर दिखाया, जो समाज के लिए प्रेरणा बन गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। निर्देश स्पष्ट थे-किसी भी हालत में राहत कार्य में कमी न आए और जनहानि न हो। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह और एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह स्वयं मोर्चा संभालते हुए मौके पर पहुंचे। पूरी प्रशासनिक टीम और एसडीआरएफ के जवान आग बुझाने और लोगों को बाहर निकालने में जुट गए।

इस पूरे अभियान में कुछ जांबाज़ युवाओं ने असाधारण साहस दिखाया। श्री सोमेश साव, श्री देवाशिष बरिहा, श्री आकाश साहू, श्री विशाल यादव, श्री अभिषेक सिन्हा और श्री ए. वेनूगोपाल ने बिना अपनी जान की परवाह किए, धधकते धुएँ और आग के बीच फंसे लोगों की जान बचाई। सोमेश साव और उनकी टीम ने बेसमेंट से फायर उपकरण उठाकर सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए आग पर काबू पाया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की।

रेस्क्यू के दौरान एक दिव्यांग नागरिक को भी कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों—श्री पुष्पराज सिंह, श्री नरेंद्र मिश्रा, श्री नंदकुमार चौबे सहित पूरी टीम ने मुस्तैदी से लोगों को समझाकर सुरक्षित बाहर निकाला।

घटना के बाद, जिला प्रशासन द्वारा इन वीर युवाओं और अधिकारियों को शॉल व किताब देकर सम्मानित किया गया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा— इन बच्चों ने कठिन परिस्थिति में समाज की संस्कृति और परिवार के संस्कारों को प्रदर्शित किया है। ये हमारे शहर के गौरव हैं और पूरे समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं।

बेबीलॉन टावर की अग्नि दुर्घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि यह साहस, एकजुटता और मानवीय संवेदनाओं की मिसाल बन गई। इन जांबाज़ युवाओं और अधिकारियों ने यह साबित कर दिया कि यदि हममें सेवा और सहयोग की भावना हो, तो किसी भी आपदा पर काबू पाया जा सकता है।

रायपुर प्रेस क्लब में स्व. विनय शर्मा स्मृति फोटोग्राफी प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का समापन

रायपुर प्रेस क्लब के नेतृत्व में 3 से 9 सितंबर तक आयोजित स्व. विनय शर्मा स्मृति फोटोग्राफी प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का समापन गरिमामय माहौल में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने वरिष्ठ फोटोग्राफर स्व. विनय शर्मा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देने से की। इसके बाद अतिथियों ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

मुख्य अतिथि मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रतिभागियों की रचनात्मकता की सराहना करते हुए कहा कि फोटोग्राफी पत्रकारिता की आत्मा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पत्रकारों के हितों के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पत्रकारों की सम्मान निधि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है, जिसका लाभ वरिष्ठ पत्रकारों को शीघ्र मिलेगा।

अध्यक्षीय उद्बोधन में विधायक पुरंदर मिश्रा ने पर्यटन मंत्री से प्रेस क्लब पत्रकारों के लिए पुरी भ्रमण की व्यवस्था करने का आग्रह किया। विशिष्ट अतिथि रामावतार तिवारी ने प्रेस क्लब की परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं नई ऊर्जा का संचार करती हैं।

प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन लगातार दूसरे वर्ष किया गया। स्व. विनय शर्मा के मीडिया फोटोग्राफी में योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह आयोजन उनके नाम को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करेगा। संचालन महासचिव डा. वैभव शिव पांडेय ने किया।

कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष रमन हलवाई, संयुक्त सचिव अरविंद सोनवानी, कार्यकारिणी सदस्य सुधीर आज़ाद तंबोली, किशन लोखंडे, नदीम मेमन, पूर्व महासचिव गोकुल सोनी, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा, उचित शर्मा, रेणु नंदी, पी.सी. रथ, रत्ना पांडे, ठाकुर राम साहू समेत बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।

प्रदर्शनी 3 से 5 सितंबर तक आयोजित की गई थी, किंतु दर्शकों की मांग पर इसे 8 सितंबर तक बढ़ाया गया। इसमें 32 फोटोग्राफरों की 100 से अधिक तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। प्रतियोगिता चार श्रेणियों ङ्क 25 सालों का छत्तीसगढ़, हेरिटेज, नेचर और ड्रोन फोटोग्राफी में आयोजित की गई। निर्णायक के रूप में प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सत्यप्रकाश पांडेय (बिलासपुर), वरिष्ठ पत्रकार श्याम वेताल एवं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म मेकर देवेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे।

विजेता सूची इस प्रकार रही

25 सालों का छत्तीसगढ़ – नरेंद्र बंगाले (प्रथम), संतोष तिवारी (द्वितीय), जय पुरी गोस्वामी (तृतीय)

हेरिटेज– पंकज चौहान (प्रथम), मनोज देवांगन (द्वितीय), गोकुल सोनी (तृतीय)

नेचर– सुधीर सागर (प्रथम), विमल मिंज (द्वितीय), पंकज चौहान (तृतीय)

ड्रोन– भूपेश केसरवानी

ओवरऑल– मनोज देवांगन

समापन अवसर पर विजेताओं और प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, कैमरा बैग एवं स्व. विनय शर्मा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने हेतु उनके परिवार की ओर से विशेष प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए।

रावतपुरा मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए 55 लाख की रिश्वत

1.62 करोड़ में हुई थी डील, 3 डॉक्टर NMC से हुए ब्लैकलिस्ट

श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में 3 डॉक्टरों को एनएमसी से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। सीबीआई ने इन 3 डॉक्टरों समेत 6 लोगों को 55 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई का ऐसा दावा है कि कॉलेज को मान्यता देने के लिए 1.62 करोड़ रुपये में डील हुई थी। जिसका पर्दाफाश कर लिया गया। श्री रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के नाम पर 55 लाख रुपये रिश्वत लेने वाले तीन डाक्टरों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन डॉक्टरों सहित छह लोगों को सीबीआई ने रंगेहाथ रायपुर से एक जुलाई को गिरफ्तार किया था।

आरोपियों को विशेष सीबीआई अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए पांच दिन के रिमांड पर लिया गया। इसके साथ ही नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च की आगामी सत्र की मान्यता संबंधी सभी प्रक्रियाएं रद कर दी गई हैं।

पहले से थी मिलीभगत

सीबीआई का दावा है कि मान्यता दिलाने के लिए 1.62 करोड़ रुपये की डील हुई थी। सीबीआई की जांच में यह साफ हुआ है कि आरोपी डॉक्टरों और कुछ अफसरों ने कॉलेज प्रबंधन से मिलीभगत किया था। उन्होंने निरीक्षण से पहले ही जांच टीम की जानकारी लीक कर दी थी। इसके बाद मेडिकल कालेज ने घोस्ट फैकल्टी, नकली मरीज और फर्जी उपस्थिति जैसे फार्मूले अपनाकर निरीक्षण को अनुकूल दिखाया।

श्री रावतपुरा सरकार के कहने पर ऐसा किया गया

अदालत में पेश दस्तावेजों में दावा किया गया है कि कॉलेज संचालन समिति अध्यक्ष रविशंकर महाराज (श्री रावतपुरा सरकार) के कहने पर ऐसा किया गया। श्री रावतपुरा सरकार आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक समेत अधिकारी एनएमसी के आगामी आधिकारिक निरीक्षण के बारे में गोपनीय और अग्रिम जानकारी प्राप्त करने की साजिश में शामिल थे।

इन 6 लोगों को किया गया गिरफ्तार

1-डॉ.चैत्रा एमएस श्रीधर-श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेंगलुरू की एसोसिएट प्रोफेसर।

2-डॉ.मंजप्पा सीएन-मांड्या इंस्ट्यूट आफ मेडिकल साइंस माड्या (कर्नाटक) की प्रोफेसर और एचओडी(आर्थोपेडिक्स)

3-डॉ. अशोक शेल्के-राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग सदस्य

4-श्री सतीशा एए-निजी चिकित्सक

5-अतुल कुमार तिवारी-श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के निदेशक।

6-रविचंद्रन केएफ-(डॉ.चैत्रा के पति)

सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा

सीबीआई ने अदालत में पेश आरोप पत्र में बताया कि निरीक्षण से ठीक पहले डॉ. मंजप्पा ने अपने साथी डॉ. सतीशा एए को 55 लाख की रिश्वत हवाला के माध्यम से लेने के लिए कहा था। डॉ. मंजप्पा ने डॉ. चैत्रा से भी संपर्क कर बताया कि उनका हिस्सा डॉ. सतीशा एए घर पहुंचाएंगे।

सीबीआई ने बेंगलुरु में जाल बिछाकर एक जुलाई को 55 लाख की रिश्वत की बरामदगी की। इसमें से 16.62 लाख रुपये डॉ. चैत्रा के पति रविचंद्रन केएफ पास से और 38.38 लाख सतीशा एए के पास से बरामद किए गए। सीबीआई ने रायपुर, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 40 से अधिक ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

मंत्री जी बोलें-सरकार का यही जीरो टॉलरेंस

इस पूरे कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि भाजपा सरकार का यही जीरो टॉलरेंस है। सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, जहां गड़बड़ी होती है, वहां कार्रवाई करती है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी।

सी.पी. राधाकृष्णन बने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति...

महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को पराजित किया।यह चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद आवश्यक हुआ था। मंगलवार, 9 सितम्बर को हुए मतदान में कुल 767 वोट पड़े, जिनमें से 752 वैध और 15 अवैध घोषित हुए। रिटर्निंग ऑफिसर व राज्यसभा महासचिव पी.सी. मोदी ने घोषणा की कि, एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी प्रत्याशी रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जीत की बधाई देते हुए कहा, थिरु सी.पी. राधाकृष्णन जी का जीवन समाज सेवा और वंचित वर्गों के उत्थान को समर्पित रहा है। मुझे विश्वास है कि वे हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे और संसदीय संवाद को नई ऊंचाइयों तक ले जाए।

कौन हैं सी.पी. राधाकृष्णन

जन्म एवं शिक्षा– 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्म। उन्होंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की।

राजनीतिक शुरुआत– 16 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े और 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने।

भाजपा नेतृत्व– 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने 93 दिनों में 19,000 किमी लंबी 'रथ यात्रा' निकाली, जिसमें नदियों के एकीकरण, समान नागरिक संहिता, आतंकवाद-निरोध, अस्पृश्यता उन्मूलन और नशे के खिलाफ कानून की मांग उठाई।

संसदीय जीवन

- कोयंबटूर से दो बार भाजपा के लोकसभा सांसद रहे।
- लोकसभा में कपड़ा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे।
- सार्वजनिक उपक्रम समिति, वित्त संबंधी परामर्श समिति और स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच करने वाली विशेष समिति के भी सदस्य रहे।
- 2004 में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया।

संवैधानिक पदों पर कार्यकाल

झारखंड के राज्यपाल– महाराष्ट्र जाने से पहले डेढ़ वर्ष तक झारखंड के राज्यपाल रहे।

महाराष्ट्र के राज्यपाल– 31 जुलाई 2024 से इस पद पर कार्यरत रहे और अब उपराष्ट्रपति चुने गए।

सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि

- राधाकृष्णन तमिलनाडु की ओबीसी गौंडर जाति से आते हैं, जो राज्य की राजनीति में प्रभावशाली है।
- यह जाति तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी अन्नाद्रमुक से भी जुड़ी रही है। अन्नाद्रमुक प्रमुख ई. पलानीस्वामी भी इसी समुदाय से आते हैं।
- उन्होंने यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के अनेक देशों की यात्राएं की हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, चीन, जापान, सिंगापुर और यूएई शामिल हैं।

राजनीतिक महत्व

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राधाकृष्णन की उम्मीदवारी भाजपा की समावेशिता और क्षेत्रीय संतुलन की रणनीति को दर्शाती है। उनकी पृष्ठभूमि दक्षिण भारत के सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। सी.पी. राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति चुना जाना न केवल भाजपा की वैचारिक जड़ों की स्वीकृति है बल्कि संसदीय परंपराओं को और मजबूत करने की दिशा में एक नया अध्याय भी माना जा रहा है।

Sukanya Samriddhi Yojana: सिर्फ 35,000 के सालाना निवेश पर मिलेगा 16 लाख का फंड, जानिए किस उम्र से करना होगा इनवेस्टमेंट..

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना माता-पिता के लिए है जो अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। इसमें छोटी रकम से बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है, जो पढ़ाई और शादी के लिए फायदेमंद है.....

अगर आप अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इस योजना में निवेश करके आप छोटी-छोटी रकम से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, जो आगे चलकर उसकी पढ़ाई, शादी या अन्य जरूरतों में काम आ सकता है।

यहां समझिए कितना करना है इनवेस्टमेंट

मान लीजिए आप हर साल 35,000 अपनी बेटी के नाम पर इस योजना में जमा करते हैं। अगर आप लगातार 15 साल तक निवेश करते हैं, तो कुल जमा राशि 5,25,000 होगी। चौंकाने वाली बात ये है कि 21 साल बाद यानी मैच्योरिटी पर आपको करीब 16,16,435 मिल सकते हैं। ये रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है और सरकार की गारंटी के साथ आती है। ये योजना खासतौर पर उन माता-पिता के लिए है, जो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि समय आने पर उन्हें आर्थिक रूप से कोई परेशानी न हो। ये एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है, खासकर उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार या जोखिम वाली योजनाओं में निवेश नहीं करना चाहते हैं।

कैसे करें सुकन्या समृद्धि योजना में इनवेस्टमेंट?

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना बेहद आसान है और यह आपकी बेटी के भविष्य के लिए एक सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प है। यहां है स्टेप-बाय-स्टेप गाइड-

सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए आप किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या सरकारी/प्राइवेट बैंक (जैसे SBI, PNB, HDFC, ICICI) में जा सकते हैं।

यहां बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (जैसे आधार या पैन कार्ड), निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और खाता खोलने का फॉर्म जमा करना होता है।

इस योजना में सालाना 250 से 1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है, जिसे एकमुश्त या किस्तों में जमा किया जा सकता है। निवेश की अवधि 15 साल होती है, लेकिन खाता 21 साल में मैच्योर होता है।

वर्तमान में योजना पर लगभग 8.2% ब्याज मिलता है, जो तिमाही रूप से कंपाउंड होता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है,इसके साथ ही निवेश पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है।

ITR Return 2025: अगर आप चूके ITR की आखिरी तारीख, तो कितना लगेगा जुर्माना, जानिए नियम और रकम...

ITR Filing Last Date: सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की है। यदि निर्धारित समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया, तो टैक्सपेयर्स को जुर्माना सहित कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है...

ITR Return 2025– इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है, और अभी तक सरकार की तरफ से इसे आगे बढ़ाने की कोई जानकारी नहीं आई है।सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ढ्ढञ्जक्रफाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 रखी है। अगर आपने इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरा, तो अब आपको लेट फाइलिंग का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

कितनी लगेगी पेनल्टी?

अगर आप तय समय के बाद ढ्ढञ्जक्र फाइल करते हैं, तो आपको Belated Return भरना होगा, जिसके लिए जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग के अनुसार आय 5 लाख से अधिक है तो लेट फाइलिंग पर 5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। वहीं आय 5 लाख से कम है तो जुर्माना 1,000 तक सीमित रहेगा।ये पेनल्टी सेक्शन 234F के तहत लगाई जाती है, और इसे रिटर्न फाइल करते समय ही चुकाना होता है।

बता दें कि लेट फाइलिंग से सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि रिफंड में देरी, ब्याज का नुकसान, और आडिट की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही अगर आप लगातार रिटर्न फाइल करने में चूकते हैं, तो भविष्य में लोन या वीजा जैसी सुविधाओं में भी दिक्कत आ सकती है।

अगर आपने अभी तक ढ्ढञ्जक्रफाइल नहीं किया है, तो आपके पास अभी भी दो दिन हैं। इसलिए जल्द से जल्द अपना ITR फाइल कर दें, वरना आपको Belated Return भरना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। लेकिन जितनी जल्दी फाइल करेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा।

ITR भरने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग

ITR फाइलिंग की मौजूदा डेडलाइन को लेकर देशभर के टैक्स प्रोफेशनल्स में चिंता बढ़ती जा रही है। कई संगठनों का कहना है कि तकनीकी दिक्कतें, पोर्टल की धीमी गति और दस्तावेज़ों की तैयारी में लगने वाला समय करदाताओं के लिए चुनौती बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टैक्स बार एसोसिएशनों और अकाउंटेंट्स संगठनों ने वित्त मंत्रालय से अपील की है कि डेडलाइन को कुछ हफ्तों के लिए बढ़ाया जाए, ताकि टैक्सपेयर्स बिना दबाव के सही और समयबद्ध रिटर्न दाखिल कर सकें।

आयुष्मान योजना में पारदर्शिता और सुधार की राह पर छत्तीसगढ़...

रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हेल्थ कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना की स्थिति पर खुलकर बातचीत की। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए नामचीन डॉक्टर्स ने भी शिरकत की और बदलती जीवनशैली से जुड़ी गंभीर बीमारियों पर अपनी स्पष्ट राय रखी। स्वास्थ्य मंत्री ने न केवल सवालों के जवाब दिए बल्कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में सरकार की प्राथमिकताओं को भी सामने रखा।

देनदारी का पहाड़ और सरकार का संकल्प

मंत्री जायसवाल ने बताया कि जब वर्तमान सरकार ने कामकाज संभाला, तब आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों पर लगभग 1400 करोड़ रुपये की देनदारी थी। यह स्थिति इतनी गंभीर थी कि बीच-बीच में डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन इलाज बंद करने की चेतावनी देने लगे थे। इससे सरकार पर दबाव भी बढ़ा और आशंका बनी रहती थी कि कहीं समय पर इलाज न मिलने से आम लोगों की जान न चली जाए।

सरकार ने इस चुनौती को प्राथमिकता में रखते हुए काम किया और मात्र एक वर्ष के भीतर 2500 करोड़ रुपये का भुगतान कर बकाया दायित्व पूरा कर दिया। यह काम 31 मार्च 2025 तक किया गया। यद्यपि इसमें चार महीने की देरी हुई, लेकिन मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह देरी अनुपूरक बजट लागू होने के कारण हुई थी।

केंद्र और राज्य का योगदान

मंत्री ने बताया कि बड़े चिकित्सा संस्थानों को सीधे तौर पर भुगतान किया गया। एम्स रायपुर और मेकाहारा रायपुर को सरकार ने 500-500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से भी सहयोग मिला। अब तक 375 करोड़ और 112 करोड़ रुपये केंद्र से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार राज्य और केंद्र के सहयोग से भुगतान प्रक्रिया को गति दी गई और अस्पतालों को भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में भी उनकी सेवाओं के बदले समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

पुराने सिस्टम की खामियां और सुधार की दिशा

स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना से जुड़े सबसे संवेदनशील मुद्दे—बिल क्लियरेंस—पर खुलकर कहा कि पहले नमस्कार करने वालों को भुगतान पहले मिल जाता था। यानी पारदर्शिता और निष्पक्षता की जगह रिश्तों और जान-पहचान का प्रभाव अधिक था। यह स्थिति न केवल योजना की साख को कमजोर कर रही थी बल्कि ईमानदारी से काम करने वाले अस्पतालों और डॉक्टरों के साथ भी अन्याय कर रही थी।

सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए विशेष योजना बनाई। हालांकि, इसके लिए नियुक्त ऑडिट कंपनी ने भी ईमानदारी से काम नहीं किया और उसमें भी गड़बड़ियां सामने आईं। ऐसे में सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस कंपनी को हटा दिया और नए सिरे से दूसरा टेंडर किया।

मंत्री जायसवाल ने कहा कि जहाँ-जहाँ सुधार की आवश्यकता है, सरकार वहाँ कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। हम लगातार सुधार की दिशा में काम कर रहे हैं और हर प्रकार के सुझाव व विचारों का स्वागत है। हमारा लक्ष्य है कि आयुष्मान योजना पूरी तरह पारदर्शी और जनहितैषी बने।

बिल जीरो की दिशा में प्रयास

सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आयुष्मान योजना के तहत किसी भी अस्पताल का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य इस दिशा में काम कर रहा है ताकि भविष्य में बिल जीरो की स्थिति बनाई जा सके। इसके लिए भुगतान प्रणाली को तकनीक आधारित और समयबद्ध बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा, हम छत्तीसगढ़ को हेल्थ ट्रीटमेंट हब बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता यह है कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएँ इतनी मजबूत हों कि न केवल राज्य के लोग बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोग भी छत्तीसगढ़ में आकर बेहतर इलाज करवा सकें।

हेल्थ कॉन्क्लेव में उठे सवाल और सुझाव

हेल्थ कॉन्क्लेव में शामिल डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा कि आधुनिक जीवनशैली ने मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा, तनाव और कैंसर जैसी बीमारियों को तेजी से बढ़ा दिया है। डॉक्टरों ने माना कि इलाज के साथ-साथ जागरूकता, परहेज़ और समय पर जांच बेहद जरूरी है।

स्वास्थ्य मंत्री ने इन सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सरकार केवल इलाज पर ही नहीं बल्कि रोकथाम और जागरूकता अभियानों पर भी जोर देगी। स्कूलों और कॉलेजों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाने की योजना है।

ट्रांसपेरेंसी और विश्वास की ओर कदम

आयुष्मान भारत जैसी विशाल योजना केवल तभी सफल हो सकती है जब आम जनता और अस्पतालों दोनों का इसमें विश्वास बना रहे। भुगतान समय पर हो, इलाज कैशलेस और सरल हो, और कोई भी मरीज केवल पैसे के अभाव में जीवनरक्षक उपचार से वंचित न रह जाए।

मंत्री जायसवाल ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस दिशा में पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की टीम जल्द ही प्रदेश का दौरा करेगी और इस दौरान अस्पतालों व डॉक्टरों को अपनी समस्याएँ सीधे रखने का मौका मिलेगा। इससे राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर समाधान की प्रि या तेज होगी।

आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य हर नागरिक को कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते एक वर्ष में बकाया भुगतान की चुनौती को जिस संकल्प और गति से पूरा किया है, वह उल्लेखनीय है। हालांकि रास्ते में चुनौतियाँ हैं—जैसे सिस्टम की पारदर्शिता, भुगतान प्रक्रिया की गति, और भ्रष्टाचार पर लगाम—but सरकार के प्रयास और मंत्री जायसवाल की स्पष्ट कार्ययोजना से यह उम्मीद जगती है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ वास्तव में हेल्थ ट्रीटमेंट हब बनकर उभरेगा।

जनता और डॉक्टरों का भरोसा बनाए रखना ही इस योजना की असली सफलता होगी। और यही भरोसा इस सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य भी है।

अमेरिका और भारत का तनाव कम होने के आसार, ट्रंप और मोदी ट्रेड डील पर जल्द करेंगे बातचीत...

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर चल रही तनातनी अब खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि उनका प्रशासन भारत के साथ व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। भारत और अमेरिका की दोस्ती जल्द ही पटरी पर लौटने के आसार नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत काफी सकारात्मक दौर में है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गये 50 फीसद की टैरिफ में भारी कटौती को लेकर जल्द ही कदम उठाये जाने जाने की संभावना जताई जा रही है। इन बातों के संकेत बुधवार भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिये हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (9 सितंबर 2025) को सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखा, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगले हफ्ते बिजनेस के सिलसिले में बात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार है। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार से संबंधित बातचीत भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का रास्ता खोलेगी।

व्यापार प्रतिनिध मंडल के अमेरिका जाने की संभावना

अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि भारत का एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते अमेरिका रवाना हो सकता है। यह दल दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं पर चर्चा करेगा और ऐसा समझौता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा जो दोनों देशों के लिए व्यापार की स्थिति सामान्य बनी रहे। भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपने अधिकारियों को व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने का निर्देश दे रहे हैं।

अमेरिका और भारत के रिश्तों में सुधार

यह सकारात्मक संकेत उस समय आए हैं, जब दोनों देशों के बीच अमेरिका द्वारा भारत पर 50 फीसद टैरिफ और रूस से तेल खरीद को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया था। ट्रंप ने पहले दावा किया था कि भारत और रूस को उन्होंने चीन के हाथों खो दिया है। जिसके बाद इन बयानों ने कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। इसके अलावा ट्रंप के कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो की तरफ से भी भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी की जा रही थी।

GST Rate Cuts:जीएसटी में कटौती के बाद 65 कारें हो जाएंगी सस्ती, यहां देखिए पूरी लिस्ट

GST Rate Cuts: केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती कर दी है। यह नया नियम 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। सरकार ने अब सिर्फ दो ही टैक्स स्लैब रखे हैं। इसमें एक 5 फीसदी और दूसरा 18 फीसदी है। इस कटौती से कई कारें सस्ती हो जाएंगी। आइये जानते किस कार के कितने कम हुए दाम

GST Rate Cuts:

केंद्र सरकार की जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर 2025 को आयोजित अपनी 56वीं बैठक में मौजूदा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में बड़े बदलावों का ऐलान किया है। सरकार ने अब सिर्फ 5 फीसदी और 18 फीसदी का जीएसटी स्लैब रखा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कारों का जीएसटी स्लैब में बदलाव कर दिया है। सरकार के इस फैसले से ऑटोमेटिव सेक्टर सुर्खियों में छा गया है। सरकार ने छोटी कारों में जीएसटी घटाकर 18 फीसदी कर दिया है। वहीं लग्जरी गाड़ियों पर 40व टैक्स लगेगा। इससे बहुत सी कारें सस्ती हो जाएंगी।

छोटी कारों पर तस्ज्ञ दर को पहले के 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है। इसके अलावा पहले की व्यवस्था में कारों पर सेस भी लगता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। छोटी कारों से मतलब हैं चार पहिया वाहन जिसकी इंजन क्षमता 1,200 सीसी तक और लंबाई 4,000 मिमी (4 मीटर से कम) हो। डीजल वाहनों के लिए यह इंजन क्षमता 1,500 सीसी तक और लंबाई 4,000 मिमी तक की सीमा है।

जीएसटी कटौती से कारें हो गईं सस्ती

1. टोयोटा फॉर्च्यूनर- अब एक्स-शोरूम कीमत से 3.49 लाख कम।
2. टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर- अब एक्स-शोरूम कीमत से 3.34 लाख कम।
3. टोयोटा हिलक्स पिक-अप- अब एक्स-शोरूम कीमत से 2.53 लाख कम।
4. टोयोटा वेलफायर एमपीवी- अब एक्स-शोरूम कीमत से 2.78 लाख कम।
5. टोयोटा इनोवा क्रिस्टा- अब एक्स-शोरूम कीमत से 1.81 लाख कम।
6. टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस- अब एक्स-शोरूम कीमत से 1.16 लाख कम।
7. टोयोटा ग्लैंज़ा- अब एक्स-शोरूम कीमत पर 85,300 सस्ती।

8. टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइज़र- अब एक्स-शोरूम कीमत पर 1.11 लाख सस्ती।
9. टोयोटा रुमियन एमपीवी- अब एक्स-शोरूम कीमत पर 48,700 सस्ती।
10. टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर- अब एक्स-शोरूम कीमत पर 65,400 सस्ती।
11. महिंद्रा बोलेरो - अब एक्स-शोरूम कीमत पर 1.27 लाख सस्ती।
12. महिंद्रा बोलेरो नियो - अब एक्स-शोरूम कीमत पर 1.27 लाख सस्ती।
13. महिंद्रा XUV xXO (पेट्रोल) - अब एक्स-शोरूम कीमत पर 1.4 लाख सस्ती।
14. महिंद्रा XUV xXO (डीज़ल) — अब एक्स-शोरूम कीमत से 1.56 लाख कम।
15. महिंद्रा थार 2WD (डीज़ल) — अब एक्स-शोरूम कीमत से

1.35 लाख कम।

16. महिंद्रा थार 4WD (डीज़ल) — अब एक्स-शोरूम कीमत से 1.01 लाख कम।
17. महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक — अब गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत से 1.01 लाख कम।
18. महिंद्रा स्कॉर्पियो एन — अब एक्स-शोरूम कीमत से 1.45 लाख कम।
19. महिंद्रा थार रॉक्स — अब एक्स-शोरूम कीमत से 1.33 लाख कम।
20. महिंद्रा XUV 700 — अब एक्स-शोरूम कीमत से 1.43 लाख कम।
21. टाटा टियागो — अब एक्स-शोरूम कीमत से 75,000 कम।
22. टाटा टिगोर — अब एक्स-शोरूम कीमत से 80,000 कम।
23. टाटा अल्ट्रोज़ — अब एक्स-शोरूम कीमत से 1.10 लाख कम।
24. टाटा पंच — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 85,000 सस्ती।
25. टाटा नेक्सन — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 1.55 लाख सस्ती।
26. टाटा कर्व — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 65,000 सस्ती।
27. टाटा हैरियर — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 1.4 लाख सस्ती।
28. टाटा सफारी — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 1.45 लाख सस्ती।
29. रेनॉल्ट ट्राइबर — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 80,195 तक सस्ती।
30. रेनॉल्ट काइगर — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 96,395 तक सस्ती।
31. रेनॉल्ट क्विड — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 54,995 तक सस्ती।
32. BMW X7 — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 9 लाख सस्ती।
33.BMW X5 — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 6.3 लाख सस्ती।
34. BMW X1 — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 1.80 लाख सस्ती।
35. BMW 5 LWB — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 4.10 लाख सस्ती।
36. BMW 2 सीरीज़ ग्रैन कूपे — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 1.60 लाख सस्ती।
37. BMW 3 LWB — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 3.40 लाख सस्ती।
38. मारुति सुजुकी ऑल्टो — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 40,000-50,000 सस्ती।
39. मारुति सुज़ुकी वैगन आर — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 60,000-67,000 सस्ती।
40. ऑडी Q3 — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 3.07 लाख सस्ती।
41. ऑडी A4 — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 2.69 लाख सस्ती।
42. ऑडी Q| — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 6.15 लाख सस्ती।
43. ऑडी Qz — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 4.55 लाख सस्ती।
44. ऑडी A6 — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 3.64 लाख सस्ती।
45. ऑडी Q8 — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 8 लाख सस्ती।
46. हुंडई ग्रैंड i10 निओस — अब एक्स-शोरूम कीमत पर ?73,808 तक सस्ती।
47. हुंडई ऑरा — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 78,465 तक सस्ती।
48. हुंडई एक्सेंट — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 89,209 तक सस्ती।
49. हुंडई i20 — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 98,053 तक सस्ती।
50. हुंडई i20 N — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 1,08,116 तक सस्ती।
51. हुंडई वेन्यू — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 1,23,659 तक सस्ती।
52. हुंडई वेन्यू ह — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 1,19,390 तक सस्ती।
53. हुंडई वरना — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 60,640 तक सस्ती।
54. हुंडई क्रेटा — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 72,145 तक सस्ती।
55. हुंडई क्रेटा एन — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 71,762 तक सस्ती।
56. हुंडई अल्काज़ार — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 75,376 तक सस्ती।
57. हुंडई टक्सन — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 2,40,303 तक सस्ती।
58. मर्सिडीज एस-क्लास 450 4मैटिक — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 11 लाख सस्ती।
59. मर्सिडीज जीएलएस 450डी एएमजी — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 10 लाख सस्ती।
60. मर्सिडीज जीएलई 450 4मैटिक — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 8 लाख सस्ती।
61. मर्सिडीज ई-क्लास LWB 450 4MATIC — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 6 लाख सस्ती।
62. मर्सिडीज A 200d — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 2.6 लाख सस्ती।
63. मर्सिडीज GLA 220d yMATIC AMG — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 3.8 लाख सस्ती।
64. मर्सिडीज C 300 AMG — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 3.7 लाख सस्ती।
65. मर्सिडीज GLC 300 4MATIC — अब एक्स-शोरूम कीमत पर 5.3 लाख सस्ती।

जीएसटी कटौती पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 1,500 सीसी से ऊपर के यात्री वाहन (एसयूवी) भी सस्ते हो गए हैं, क्योंकि अब उन पर 40% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले उन पर 28% जीएसटी और 22% उपकर लगता था। इससे एसयूवी अंतिम उपभोक्ता के लिए सस्ते हो जाएंगे।

सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025- पितृ अमावस्या पर लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत से नहीं दिखेगा...

साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण आगामी 21 सितंबर को लगने जा रहा है। खास बात यह है कि यह दिन पितृ अमावस्या पर पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ अमावस्या पर श्राद्ध, तर्पण, दान और ब्राह्मण भोज जैसे कर्म किए जाते हैं। जब इस तिथि पर सूर्य ग्रहण पड़े तो दान-पुण्य का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

ग्रहण का समय और दृश्यता

ज्योतिषाचार्य आनंद भारद्वाज (उज्जैन) के अनुसार, भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण रात 10.59 बजे शुरू होकर अगले दिन सुबह 3.23 बजे तक रहेगा।

- भारत से यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा।
- यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, पोलिनेशिया, मेलानेशिया और एशिया के कुछ हिस्सों से देखा जा सकेगा।
- न्यूज़ीलैंड के ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन और नॉरफ़ॉक द्वीप का किंग्स्टन शहर प्रमुख स्थान होंगे, जहाँ से यह ग्रहण साफ़ दिखाई देगा।

भारत में सूतक काल लागू नहीं होगा

चूंकि भारत से यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा। भक्तजन इस दिन बिना किसी रोक-टोक के पूजा-पाठ और धार्मिक कर्म कर सकेंगे।

- श्राद्ध और तर्पण कर्म सामान्य रूप से किए जा सकेंगे।
- उपवास और पूजा-पाठ पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

परंपरागत मान्यता

हिंदू धर्म में परंपरा रही है कि सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। स्नान, दान और पूजा जैसे कर्म ग्रहण समाप्त होने के बाद ही किए जाते हैं, ताकि ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है।

ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि यद्यपि यह ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा, फिर भी गर्भवती महिलाओं को सूर्य की किरणों से बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। परंपरा के अनुसार ग्रहण काल में विशेष परहेज़ और सुरक्षा का ध्यान रखना शुभ माना गया है।

धार्मिक महत्व

पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का पड़ना विशेष महत्व रखता है।

श्राद्ध और तर्पण के साथ किया गया दान-पुण्य कई गुना फलदायी माना जाता है। ब्राह्मण भोज और गरीबों को अन्न-वस्त्र दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन पितरों को स्मरण करने और कृतज्ञता व्यक्त करने का उत्तम अवसर है।

इस प्रकार, 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन पितृ अमावस्या के कारण यह दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। श्रद्धालु सामान्य पूजा-पाठ और दान-पुण्य के कार्य कर सकेंगे, जबकि ज्योतिषाचार्यों ने विशेषकर गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की सलाह दी है।

GST सुधार से नहीं घटेगा राजस्व, 6.8 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ेगी जीडीपी...

जीएसटी स्लैब में कटौती से सरकार को कोई राजस्व घाटा नहीं होगा । खपत बढ़ने से अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि होगी । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कई वस्तुओं पर कर दरों में कटौती के बाद खपत से 48000 करोड रुपए की जीएसटी कमी की भरपाई हो जाएगी। इसलिए राजकोषीय घाटे या राजकोषीय प्रबंधन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा ।

सीतारमण ने एक साक्षात्कार में कहा, ऐतिहासिक जीएसटी सुधार से चालू वित्त वर्ष (2025- 26) में अनुमानित वृद्धि दर के 6.3- 6.8 फीसदी के पार करने में मदद मिल सकती है ।

48000 करोड रुपए का वित्तीय प्रभाव आधार वर्ष पर आधारित एक स्थिर संख्या है । लेकिन जब इसे लागू किया जाता है, तो आधार स्थिति बदल जाती है। मुझे लगता है कि 22 सितंबर से खपत में वृद्धि से आय में उछाल आएगा । इसलिए विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने से देश के हर वर्ग के परिवारों को लाभ होगा ।

यह पूछे जाने पर की क्या उपभोग में वृद्धि और पहली तिमाही में अपेक्षा से बेहतर ।.8त्न जीडीपी आंकड़ों के आधार पर चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी अनुमान में वृद्धि की जा सकती है, वित्त मंत्री ने कहा, संभव है, बहुत संभव है ।सीतारमण ने कहा सरकार विनिमय दरों पर अच्छी नजर रख रही है । रुपए के अलावा कई अन्य मुद्राओं का डॉलर के मुकाबले अवमूल्यन हुआ है । रुपया रिकॉर्ड 88.2। पर बंद हुआ । रुपए में गिरावट मुख्यत: डॉलर के मुकाबले है, किसी अन्य मुद्रा के मुकाबले नहीं । ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वैश्विक स्तर पर डॉलर मजबूत हुआ है ।

जीएसटी दरों में कमी को लेकर पहली बार चर्चा पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इशारे में कहा था, एक बार आप जीएसटी को देख लो । इसी शब्द से उलझी हुई वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में विशाल परिवर्तन किया गया ।

हालांकि प्रधानमंत्री ने बजट तैयार करते समय भी सीतारमण से पूछा था कि आप जीएसटी के ऊपर कर रही हैं ना काम ? प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के बाद सीतारमण ने जीएसटी की समीक्षा शुरू कर दी । इसमें न सिर्फ दरें और टैक्स स्लैब बल्कि व्यवसायों, खासकर छोटे और मध्यम कारोबारी इसे कैसे अपनाएंगे, इस पर भी विचार किया गया। वित्त मंत्री ने कहा, मैंने निर्णय लिया कि जीएसटी से जुड़ी हर चीज की गहन समीक्षा होनी चाहिए । 1 फरवरी 2025 से लेकर 15 मई तक अध्ययन और समीक्षा की गई । मई में मोदी को बताया, हम एक प्रस्ताव तैयार किए हैं। आप समय दें, ताकि उसकी जानकारी दे सकूं। सीतारमण का ध्यान अब कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा। कार्यान्वयन 22 सितंबर से कम से कम एक-दो दिन पहले बैकएंड सॉफ्टवेयर बदलाव के लिए तैयार हो जाएगा ।

दरें कम नहीं हुई तो उद्योग संगठनों से की जायेगी शिकायत

जीएसटी की घाटी हुई दरें लागू होने के बाद 22 सितंबर से वस्तुओं की कीमतों में कमी नहीं आती है। तो संबंधित शिकायतों को बोर्ड उद्योग निकायों के समक्ष उठाएगा । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीएसई के प्रमुख संजय कुमार अग्रवाल ने कहा, उद्योग ने पहले भी जब भी जीएसटी परिषद के करो में कमी का फैसला लिया है ,वस्तुओं की कीमतें कम की है । हमें विश्वास है कि उद्योग इसका लाभ अंतिम उपभोक्ताओं पर पहुंच जाएगा । कोई शिकायत मिलती है तो उसे उद्योग निकाय के समक्ष उठाएंगे । मुनाफाखोरी की शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था पहले भी थी।

जितिया व्रत- संतान की दीर्घायु और कल्याण के लिए माताओं का महापर्व...

भारतीय संस्कृति में व्रत और त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं होते, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों से भी गहराई से जुड़े होते हैं। संतान की दीर्घायु और उनके कल्याण की कामना से जुड़ा जितिया व्रत (जीवितपुत्रिका व्रत) मातृ-समर्पण का अनुपम उदाहरण है। यह व्रत मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा नेपाल के मिथिला और थरुहट क्षेत्र सहित मधेसी और थारू समुदायों में अत्यधिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है।

आलेख
राखी श्रीवास्तव

व्रत का समय और स्वरूप

यह व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तिथि तक तीन दिनों तक चलता है।

पहला दिन- नहाय-खाय- इस दिन व्रती महिलाएं स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं और अगले दिन के कठोर उपवास की तैयारी करती हैं।

दूसरा दिन- खुर जितिया- इस दिन माताएं निर्जला उपवास करती हैं। न भोजन, न जल- पूरे दिन और रात यह कठिन व्रत रखा जाता है।

तीसरा दिन - पारण- नवमी तिथि को व्रत का समापन विशेष भोजन से किया जाता है। क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार पारण में नोनी का साग, मारुआ या मडुआ की रोटी, तोरी की सब्जी, मछली और भोर (करी-चावल) का विशेष महत्व है।

व्रत के नियम

- व्रती महिलाएं उपवास के दिन पानी तक नहीं पीतीं।
- इस व्रत में सोया और कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है।
- पूरा व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना के लिए करती हैं।

व्रत का सांस्कृतिक महत्व

यह पर्व सामूहिकता और मातृत्व के अद्भुत संगम का प्रतीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सामूहिक रूप से व्रत करती हैं और प्राचीन लोककथाओं, गीतों तथा रीति-रिवाजों का पालन करती हैं। जितिया गीत और लोकनृत्य भी इस अवसर पर प्रचलित हैं, जो सामुदायिक उत्सव का रूप देते हैं।

जितिया व्रत की कथाएं

1. गरुड़ और लोमड़ी की कथा

कहानी के अनुसार एक समय गरुड़ (चील) और मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास जंगल में रहते थे। उन्होंने कुछ महिलाओं को व्रत करते देखा और स्वयं भी इसे करने का निश्चय किया।

- उपवास के दौरान लोमड़ी भूख से व्याकुल होकर चोरी-छिपे भोजन कर बैठी।
- जबकि गरुड़ ने पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ व्रत का पालन किया।

फलस्वरूप, लोमड़ी की संतान अल्पायु हुई और गरुड़ की संतान दीर्घायु व समृद्ध हुई। यही संदेश इस कथा से मिलता है कि व्रत की पवित्रता और सच्ची निष्ठा से संतान को आशीर्वाद प्राप्त होता है।

2. जीमूतवाहन की कथा

जीमूतवाहन गंधर्व वंश के ज्ञानी और दयालु राजा थे। उन्होंने राज-पाट छोड़कर अपने पिता की सेवा और तपस्या के लिए वनवास ग्रहण किया। एक दिन उन्हें एक वृद्धा विलाप करती मिली। उसने बताया कि वह नागवंशी है और प्रतिदिन गरुड़ को भोजन स्वरूप एक नाग दिया जाता है। उस दिन उसका इकलौता पुत्र भक्ष्य बनने वाला था। जीमूतवाहन ने करुणा और साहस दिखाते हुए स्वयं को वृद्धा के पुत्र के स्थान पर बलिदान के लिए प्रस्तुत कर दिया। जब गरुड़ ने जीमूतवाहन को पकड़ लिया, तो उसने सत्य प्रकट किया।

जीमूतवाहन की त्याग भावना और वीरता से प्रभावित होकर गरुड़ ने वचन दिया कि वह आगे से किसी नाग का भक्षण नहीं करेगा। इस घटना ने त्याग, परोपकार और संतानों की रक्षा का आदर्श प्रस्तुत किया।

धार्मिक और सामाजिक महत्व

- यह व्रत माताओं के त्याग, प्रेम और समर्पण का जीता-जागता उदाहरण है।
- यह पर्व समाज में सामूहिकता, सहयोग और लोक परंपराओं के संरक्षण का प्रतीक है।
- जितिया व्रत के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों में संतान-स्नेह और पारिवारिक मूल्यों का संवर्धन होता है।

इस प्रकार जितिया व्रत केवल धार्मिक कर्मकांड भर नहीं है, बल्कि मातृत्व की शक्ति, त्याग और संतानों के प्रति निस्वार्थ प्रेम का अद्वितीय पर्व है। यह त्योहार समाज को यह शिक्षा देता है कि सच्चे समर्पण और आस्था से जीवन के कठिन से कठिन लक्ष्य भी सहज बन सकते हैं। मिथिला और भोजपुरी अंचल से लेकर नेपाल तक इसकी लोकप्रियता माताओं की अटूट आस्था और संतान-स्नेह का प्रमाण है।

बदलते चरित्र और बदलते रिश्ते...

समय की चाल में सब कुछ बदल जाता है,
चरित्र भी, रिश्ता भी नया रूप पा जाता है।

चरित्र का आईना अब धुंधला नज़र आता है,
लोभ में इंसान अपना चेहरा खो जाता है।

कल जो साया था, आज धूप हो गया,
जो अपना था, वही अनूप हो गया।

मुस्कान में छिपे थे जो सच्चे अहसास,
अब उनमें दिखते हैं केवल बनावटी पास।

जो रिश्ते पहले नज़र से समझ जाते थे,
आज शब्दों के बोझ तले दब जाते हैं।

समर्पण की जगह स्वार्थ ने ले ली है,
विश्वास की जड़ें अब सूख चली हैं।

वक़्त ने चेहरों पर नक़ाब सजा दिए,
सपनों के दरवाज़े ख़ुद ही बंद कर दिए।

रिश्तों का धागा कभी मज़बूत, कभी ढीला,
सच की जगह अब लगता है सब फीका।

फिर भी उम्मीद का दीप बुझने मत देना,
सच्चाई का रिश्ता जीवन में चुन लेना।

क्योंकि बदलते दौर में भी एक बात सच रहती है,
ख़ालिस चरित्र और सच्चा रिश्ता कभी नहीं ढहती है।

(भूषण)

त्वचा और बालों के लिए अनार के अद्भुत फायदे

अनार, जिसे अक्सर स्वर्ग का फल कहा जाता है, एक चटक लाल फल है जो पोषक तत्वों से भरपूर छोटे र जैसे बीजों से भरा होता है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन (खासकर विटामिन सी), खनिज और प्राकृतिक अम्लों से भरपूर अनार सदियों से सौंदर्य प्रसाधनों में मूल्यवान रहा है। त्वचा के लिए, यह बढ़ती उम्र के लक्षणों से लड़ने में मदद करता है, चमक बढ़ाता है और बालों को स्वस्थ बनाता है, जबकि बालों के लिए, यह स्कैल्प को पोषण देता है, बालों को मज़बूत बनाता है और प्राकृतिक चमक बढ़ाता है। चाहे ताज़ा इस्तेमाल किया जाए, जूस के रूप में, या तेल और अर्क के रूप में, अनार एक प्राकृतिक तत्व है जो त्वचा को फिर से जीवंत, सुरक्षित और गहराई से पोषण दे सकता है, जिससे यह त्वचा और बालों की देखभाल में एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है।

त्वचा के लिए लाभ- एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

पॉलीफेनॉल, एंथोसायनिन और विटामिन सी से भरपूर, जो मुक्त कणों से लड़ने, समय से पहले बूढ़ा होने की प्रक्रिया को धीमा करने और त्वचा को पर्यावरणीय क्षति से बचाने में मदद करते हैं। कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है- अनार में मौजूद विटामिन सी और एलाजिक एसिड कोलेजन संश्लेषण में मदद करते हैं, जिससे त्वचा दृढ़, कोमल और जवां बनी रहती है। त्वचा की रंगत निखारता है- प्राकृतिक एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की चमक बढ़ाते हैं, रूखेपन को कम करते हैं और रंगत को एक समान बनाते हैं।

Also Read - Spicy Dal Khichdi: घर पर बनाएं लाजवाब चटाकेदार दाल खिचड़ी त्वचा को हाइड्रेट और मुलायम बनाता है- अनार के बीज का तेल त्वचा में गहराई तक प्रवेश करता है, नमी बनाए रखता है और रूखेपन को रोकता है। सूजन और मुँहासों को कम करता है- इसके सूजनरोधी और रोगाणुरोधी गुण त्वचा की जलन को कम करते हैं और मुँहासा पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। सूरज की क्षति से बचाता है- एंटीऑक्सीडेंट यूवी किरणों के प्रभाव को कम करने और टैनिंग व पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करते हैं।

Also Read - Recipe: घर पर आसानी से बनाएं स्मोकी अनियन क्रंची मैक एंड चीज़ त्वचा के पुनर्जनन को बढ़ावा देता है- कोशिकाओं के नवीकरण को उत्तेजित करता है, घावों, दाग-धब्बों और दाग-धब्बों को तेज़ी से भरने में मदद करता है। बालों के लिए लाभ- बालों के रोमछिद्रों को मज़बूत बनाता है- विटामिन ष्ट स्कैल्प में कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे बाल जड़ों से मज़बूत होते हैं। बालों के विकास को बढ़ावा देता है- अनार के बीज के तेल में मौजूद प्यूनिकिक एसिड स्कैल्प में रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जिससे बालों का विकास होता है।

Also Read - मकरासन से मिलेगी शांति, आयुष मंत्रालय ने बताया इसका सही तरीका और फायदे बालों का झड़ना रोकता है- आयरन, विटामिन श्व और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व बालों के रोमछिद्रों को पोषण देते हैं, जिससे बालों का पतला होना कम होता है। चमक और कोमलता प्रदान करता है- इसके प्राकृतिक तेल बालों के तने पर परत चढ़ाते हैं, जिससे बालों को चमकदार और उलझे हुए बालों से मुक्त लुक मिलता है।

कुछ चटपटा खाने का कर रहा है मन ? तो घर पर बनाएं स्ट्रीट स्टाइल कटोरी चाट...

(स्वादिस्ट - चटपटी कटोरी चाट)

त्योहारों का मौसम है, ऐसे में आप भी अपने घर आने वाले मेहमानों को कुछ अलग और चटपटा बनाकर खिलाना चाहते हैं, तो शेफ के स्टाइल में कटोरी चाट बनाकर उन्हें खिला सकते हैं, तो कटोरी चाट बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। हमारे देश में हर शहर का अपना जायका है, चाट को भी कई अलग-अलग स्टाइल में बनाया जाता है। कहीं लोग पापड़ी चाट खाना पसंद करते हैं तो कहीं समोसा चाट तो कहीं टिक्की वाली चाट। हालांकि ये स्पेशल कटोरी चाट रेसिपी हर किसी को जरूर पसंद आएगी। कटोरी चाट बनाना जानते हैं।

कटोरी चाट

तैयारी का समय- 30 मिनट, पकाने का समय- 30 मिनट

आवश्यक सामग्री निम्नानुसार

- कटोरी के लिए-1 कप मैदा,
- 2 बड़े चम्मच मक्के का आटा,
- 1/2 बड़ा चम्मच अजवायन,
- 2 बड़े चम्मच तेल,
- 1/2 छोटा चम्मच नमक,
- पानी (आवश्यकतानुसार),

हरी चटनी के लिए

- 1/2 कप कटा हरा धनिया,
- 3-4 हरी मिर्च,
- 2 टेबल स्पून भुने चने,
- 1 अदरक,
- 2 बड़े चम्मच नींबू का रस,
- नमक स्वादानुसार,
- 2 बड़े चम्मच दही

दही के लिए

● 2 कप दही, ● 2 बड़े चम्मच चीनी, ● 1 छोटा चम्मच नमक

चाट के लिए

- 1 कप उबले चना, 2 उबले आलू

परोसने के लिए

1/2 कप प्याज बारीक कटा हुआ, 1/2 कप टमाटर, कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच धनिया

पत्ती,1/2 कप सेव, 1/2 कप इमली की चटनी, 1/2 कप अनार, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला 7

बनाने की विधि

मैदा में देसी घी, नमक, अजवाइन डालकर अच्छी तरह मल लें। सख्त लेकिन चिकना आटा बनाने के लिए पर्याप्त पानी डालें । आटे को 20 मिनट के लिए रख दें और फिर से एक मिनट के लिए गूंथ लें । आटे को बॉल्स में तोड़ लें । बॉल्स को पतला बेल लें । कुकी कटर या कटोरी का उपयोग करके, आटे को गोल काट लें । एक कांटा चम्मच के साथ डिस्क में छेद कर लें । इस डिस्क को स्टील के गिलास या कटोरी के बेस पर रखें ।

एक कड़ाही में तेल गरम करें । मध्यम गरम तेल में डिस्क को डालें और हल्का रंग आने तक तलें । अब कटोरी या गिलास निकाल लें, मैदे का बना डिस्क कटोरी के शेप में आ जाएगा, इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलें । दही को छलनी से छान लें और उसमें 2 टेबल स्पून चीनी और 2 टीस्पून नमक मिला लें । चटनी की सभी सामग्री को एक साथ मिला लें और पीसकर मुलायम पेस्ट बना लें । अब सर्व के लिए कटोरी के बेस पर मीठा दही लगाएं । इसके ऊपर क्यूब किए हुए आलू, उबले चना डाल दीजिए । अब इसके ऊपर दही, हरी चटनी और इमली की मीठी चटनी डालिये । ऊपर से कटे हुए प्याज, टमाटर, अनार के दाने, सेव, चाट मसाला डालें और इसे सर्व करें ।

रेसीपी

जी.व्ही.एस. रुक्मणि देवी

नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल संग होते हैं 50 फीसदी हार्ट अटैक, हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी हैं ये 5 टेस्ट्स....

कोलेस्ट्रॉल स्तर नॉर्मल होने पर भी हार्ट अटैक का खतरा रहता है। एलडीएल और एचडीएल जैसी रिपोर्ट अधूरी होती हैं। नर्म प्लाक अधिक खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए व्यापक जांच जरूरी है। लगभग आधे हार्ट अटैक उन लोगों को होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल स्तर नॉर्मल माना जाता है। यही बात इस सोच पर सवाल उठाती है कि सिर्फ़ कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट देखकर ही हार्ट डिज़ीज का पता लगाया जा सकता है।

अक्सर डॉक्टर एलडीएल, एचडीएल, कुल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसी रिपोर्ट पर ज़ोर देते हैं। लेकिन यह तरीका अधूरा है, क्योंकि हार्ट डिज़ीज का खतरा सिर्फ़ कोलेस्ट्रॉल से तय नहीं होता। इसमें सूजन, जेनेटिक फैक्टर, खून की नलियों में बनने वाला प्लाक और उसकी क्वालिटी (सख़्त या नर्म) भी अहम होते हैं।

यहाँ तक कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, उनकी धमनियों (arteries) में भी ख़तरनाक मात्रा में प्लाक हो सकता है। और अगर यह प्लाक नर्म और आसानी से फटने वाला है, तो अचानक धमनी बंद होकर हार्ट अटैक हो सकता है। कैल्शियम स्कोर टेस्ट सिर्फ़ सख़्त और कैल्शियम-युक्त प्लाक दिखाता है, लेकिन नर्म और ख़तरनाक प्लाक को पकड़ नहीं पाता।

सिर्फ़ कोलेस्ट्रॉल ही सब कुछ नहीं

एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यह नहीं बताता कि धमनियों में प्लाक बना है या नहीं, वह किस प्रकार का है और फट सकता है या नहीं। असली रिस्क समझने के लिए शरीर की धमनियों की स्थिति और उनमें हो रही सूजन का पता लगाना जरूरी है।

कॉर्नेल-ट्रेंड डॉक्टर वासिली इलियोपोलोस का मानना है कि सिर्फ़ एलडीएल देखना ग़लत सुरक्षा का अहसास देता है। यह तो कई फैक्टर्स में से बस एक है।

जानिए जरूरी टेस्ट के बारे में- हार्ट हेल्थ को सच में समझने के लिए ये जांचें ज़्यादा अहम मानी जाती हैं-

एपोलिपोप्रोटीन B (ApoB): यह टेस्ट खतरनाक कणों (particles) की गिनती बताता है, जो प्लाक जमने की वजह बनते हैं। यह एलडीएल से ज़्यादा सटीक जानकारी देता है।

पोप्रोटीन(a): यह जेनेटिक टेस्ट है। अगर यह बढ़ा हो तो हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है, भले ही बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल हों।

हाई सेंसिटिविटी C- रिएक्टिव प्रोटीन (hs-CRP) और होमोसिस्टीन- ये टेस्ट शरीर की सूजन और नलियों के तनाव का पता लगाते हैं।

ओमेगा-3 इंडेक्स- अगर शरीर में ओमेगा-3 की कमी है तो सूजन और हार्ट डिज़ीज़ का खतरा बढ़ जाता है।

कोरोनरी CT एंजियोग्राफी (CCTA) + AI एनालिसिस- नई टेक्नोलॉजी वाले स्कैन जैसे Cleerly नर्म और ख़तरनाक प्लाक भी दिखा सकते हैं, जिन्हें कैल्शियम स्कोर टेस्ट पकड़ नहीं पाता।

डॉ. इलियोपोलोस कहते हैं कि धमनियों में 30 प्रतिशत की नर्म रुकावट 70 प्रतिशत की सख़्त रुकावट से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि नर्म प्लाक आसानी से फट सकता है।

एन. रघुरामन का कॉलम- अनुशासित बनें या बुरी आदतों पर अधिक खर्च करें, फैसला आपका ...

एक दिन सुबह 4 बजे मैं अपनी बिल्डिंग से अपनी नियमित दूधवाला फ्लाइट (अल सुबह) के लिए निकला। बिल्डिंग का चौकीदार- जो हमेशा सोता मिलता है और विंग का अंदरूनी गेट खोलने के लिए उसे जगाना पड़ता है- आज बिल्कुल सजग था। उसने मुझे गुड मॉर्निंग भी बोला। मैं अचंभित हुआ।

एयरपोर्ट जाते समय मैंने ड्राइवर से पूछा कि वह आज इतना खुश क्यों दिख रहा है, क्या उसे सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने चेतावनी दी है? ड्राइवर ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं सर, उसने मोबाइल पर फिल्में देखना बंद कर दिया है। यह जवाब मुझे 2016 के फ्लैशबैक में ले गया, जब एक मोबाइल कंपनी ने इंटरनेट को लगभग मुफ्त करते हुए उस चीज को बढ़ावा दिया, जिसे मैं डिजिटल समाजवाद कहता हूं।

ये को-ऑपरेटिव सोसाइटी के चौकीदार धीरे-धीरे मुफ्त इंटरनेट का उपयोग कर फिल्में देखने लगे। फिर यह उनकी लत बन गई। भले ही उनकी तनख्वाह 8 से 10 हजार रुपए थी, लेकिन उन्होंने ईएमआई पर स्मार्टफोन खरीदे- जो उनकी तनख्वाह से कई गुना महंगे थे, क्योंकि वे मुफ्त इंटरनेट और फिल्में देखने के आदी हो चुके थे। जाने-अनजाने वे मान बैठे कि फिल्में देखने से वे रात को जागते रहेंगे। धीरे-धीरे यही धारणा उनकी नौकरी बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन बन गई।

अब 2025 पर आते हैं। जब कोई चीज ऑक्सीजन बन जाती है, तो कंपनियां उस उत्पाद की कीमतें बढ़ा देती हैं। भारत के लोगों का पसंदीदा नशा- मेरा मतलब डेटा- हाल ही में थोड़ा महंगा हो गया। लेकिन ऐसी दाम बढ़ोतरी उत्पाद की मांग घटाती नहीं है, क्योंकि वह तो ऑक्सीजन की श्रेणी में आता है।

असल में तो वह महत्वाकांक्षी बन जाता है। ये चौकीदार लोग मोबाइल पर जमे रहने के लिए अपनी सुबह की चाय या वड़ा पाव तक छोड़ सकते हैं। कुछ यह कहने में गर्व महसूस कर सकते हैं कि मेरे पास पर्याप्त डेटा है और मैं प्रीमियम सेवाओं के लिए भुगतान करता हूं।

यह उन स्मोकर्स की तरह है, जिनकी सिगरेट पर संशोधित जीएसटी के तहत 40त्न की उच्चतम स्लैब लगने वाली है। कुछ आकलन बताते हैं कि अभी 20 सिगरेट का जो पैकेट 340 रुपए का है, वो आगामी 22 सितंबर से 380 रुपए तक हो सकता है। यानी एक दिन में एक पैकेट पीने वाले को रोजाना 40 रुपए और महीने में 1200 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

ऑफिस के बाहर खड़े होकर धूम्रपान करने वाले कुछ वेतनभोगियों के लिए यह आय का 15 से 20त्न तक होगा, क्योंकि धूम्रपान का खर्च 11400 रुपए तक पहुंच जाएगा। अगर परिवार में दो लोग धूम्रपान करते हैं तो पूरा परिवार मिलकर अपनी कमाई का 35-40त्न तंबाकू कंपनियों को दे देता है। सिगरेट की लत और डेटा उपयोग एक जैसी बातें हैं। कई लोगों के लिए दोनों आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल होने वाला है।

बीते नौ सालों में मुफ्त और सस्ते डेटा ने हमें री-वायर्ड कर दिया है। हम अब दिशाओं को लेकर दिमाग पर जोर नहीं डालते। हम किसी से नहीं पूछते कि भैया, ये कॉलोनी कहां है? हम स्पेलिंग देखने के लिए डिक्शनरी नहीं खोलते। एक क्लिक पर कुछ साइट्स यह बता देती हैं।

गृहिणियों ने अपनी पाक कला के प्रयोग बंद कर दिए। वे हमेशा मोबाइल पर किसी शेफ की रेसिपी देखती रहती हैं। कॉलेज के बच्चों के लिए तो मोबाइल शरीर का अंग बन गया है, जिसे वे टॉयलेट में भी ले जाते हैं। संक्षेप में कहें तो मानव शरीर की मेमोरी डिस्क कहे जाने वाले हमारे मिड-ब्रेन में धूल छा रही है। क्योंकि सर्चिंग हमारी प्रवृत्ति बन गया है और सोचना वैकल्पिक हो गया है।

तो भविष्य क्या है? पहले वे आदत लगाएंगे। यदि आप उत्पाद का उपयोग और भुगतान कर रहे हैं, तो आप एक परफेक्ट यूजर होंगे। लेकिन, हममें से ज्यादातर उस सीमा को पार कर जाते हैं और एडिक्ट बन जाते हैं। फिल्में बिंज-वॉच करते हैं और धीरे-धीरे धूम्रपान की तरह लत के शिकार हो जाते हैं।

फंडा यह है कि या तो उपरोक्त चौकीदार की तरह अनुशासित बनें या उसी उत्पाद के लिए प्रीमियम भुगतान करते रहें, क्योंकि आपको लगता है कि आपने समाज में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। चयन आपका है।

इंदौर की गलियों से मैडिसन स्क्वायर तक- जाकिर खान का ऐतिहासिक सफ़र

कभी किसी छोटे से शहर की संकरी गलियों से निकला एक युवक अपनी बातों से पूरी दुनिया को हंसा सकता है–यह शायद बहुतों को एक सपना लगे। लेकिन इंदौर के जाकिर खान ने इसे सच कर दिखाया। हाल ही में जब उन्होंने न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में स्टैंड-अप शो किया, तो 6,000 से अधिक दर्शकों की गूंजती तालियों और स्टैंडिंग ओवेशन ने यह साबित कर दिया कि भारतीय कॉमेडी अब केवल देसी मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने विश्वस्तर पर पहचान बना ली है। 37 वर्षीय जाकिर खान का यह शो केवल मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह उस संघर्ष, मेहनत और जज्बे का प्रमाण भी था जिसने एक साधारण से युवा को सख़्त लौंडा से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्टार बना दिया।

शुरुआती जीवन- संगीत की गलियों से कॉमेडी का मंच

जाकिर खान का जन्म 20 अगस्त 1987 को इंदौर में हुआ। उनका परिवार संगीत से गहराई से जुड़ा है। दादा उस्ताद मोईनुद्दीन खान सरोद वादक थे और पिता एक संगीत शिक्षक। स्वाभाविक था कि जाकिर ने भी संगीत की राह पकड़ी। उन्होंने सितार में डिप्लोमा किया और शुरुआती दौर में रेडियो जॉकी तथा स्क्रिप्ट राइटिंग के क्षेत्र में काम किया। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। 2012 में उन्होंने Comedy Central का IndiaÓs Best Stand-Up जीतकर सबको चौंका दिया। यही वह मोड़ था जहां से उनके जीवन की दिशा बदल गई।

सख़्त लौंडा की पहचान

स्टैंड-अप कॉमेडी में उनकी शैली अनूठी थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की साधारण घटनाओं को वे इस तरह से पेश करते हैं कि हर व्यक्ति उनसे खुद को जोड़ पाता है।

सख़्त लौंडा उनका सबसे लोकप्रिय टैग बन गया। यह महज़ एक जोक या स्लैंग नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक प्रतीक था—दिल टूटने के बाद भी मुस्कुराना, परिस्थितियों से जूझते हुए मज़ाक करना और खुद पर हंसना।

उनके शो जैसे Haq Se Single, Kaksha Gyarvi, Tathastu और हाल ही में रिलीज़ हुआ Delulu E&press ने साबित कर दिया कि हिंदी में स्टैंड-अप भी उतना ही प्रभावशाली हो सकता है जितना अंग्रेज़ी में।

अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच

भारत के बाद जाकिर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। 2023 में उन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में शो किया, जहां उन्हें अपार सफलता मिली। और अब 2025 में, न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी स्टैंड-अप करने वाले वे पहले भारतीय बन गए।

इस ऐतिहासिक शो में दर्शकों की संख्या लगभग 6,000 रही। शो के बाद पूरे हॉल ने खड़े होकर तालियां बजाईं। स्वयं जाकिर ने भावुक होकर कहा—इंदौर का एक लड़का मैडिसन स्क्वायर तक पहुंचेगा, यह तो सपनों में भी नहीं सोचा था। यह मंच बड़े-बड़े सितारों के लिए है, लेकिन ज़िंदगी कभी-कभी ऐसा जादू कर देती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

जाकिर खान की नेट वर्थ 2025

आज जाकिर खान केवल नाम ही नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। उनकी नेट वर्थ को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं।

- Sovrenn की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 26.6 करोड़ है।
- कुछ अन्य रिपोर्ट्स इसे 30-36 करोड़ तक आंकती हैं।
- स्वतंत्र पोर्टल्स के अनुसार यह आंकड़ा 40 करोड़ तक हो सकता है।
- यानी मोटे तौर पर कहा जाए तो आज जाकिर खान की नेट वर्थ 25-40 करोड़ के बीच है।

एक शो का चार्ज और कमाई के स्रोत

जाकिर खान की कमाई केवल स्टैंड-अप शो तक सीमित नहीं है।

- लाइव शो फीस- औसतन प्रति शो 4-5.5 लाख। कुछ अंतरराष्ट्रीय या बड़े आयोजनों में यह राशि 10-15 लाख तक बताई जाती है।
- टीवी/डिजिटल शो- आपका अपना जाकिर जैसे शोज़ में प्रति एपिसोड करीब ?4 लाख।
- ब्रांड एंडोर्समेंट्स- लगभग 2-3 लाख प्रति ब्रांड या सालाना 1-2 करोड़।
- YouTube: 80 लाख से अधिक सब्सक्राइबर के साथ वे हर महीने 25-35 लाख तक कमा लेते हैं।
- OTT स्पेशल्स- अमेज़न प्राइम पर उनके शो लगातार हिट साबित हुए हैं और इससे उन्हें अच्छी आय होती है।
- पॉडकास्ट और सोशल मीडिया- उम्मीद और अन्य पॉडकास्ट से भी वे कमाई कर रहे हैं।

जाकिर खान की शैली- क्यों हैं इतने लोकप्रिय?

1. भाषा और जुड़ाव- वे हिंदी और हिंदुस्तानी अंदाज़ में कॉमेडी करते हैं, जिससे हर दर्शक जुड़ पाता है।

2. शायरी का तड़का- उनकी शायरी और गहरी बातें दर्शकों को भावुक भी करती हैं।

3. सामान्य जीवन की झलक- कॉलेज, दोस्ती, प्यार, दिल टूटने जैसी साधारण कहानियों को वे इस अंदाज़ में कहते हैं कि हर कोई हंसते-हंसते सोचने पर मजबूर हो जाता है।

4. युवा प्रतीक- हक से सिंगल जैसे डायलॉग युवाओं के लिए मज़ाक से ज्यादा एक पहचान बन गए हैं।

प्रेरणा और संघर्ष

जाकिर ने कभी खुद को असाधारण नहीं माना। उन्होंने कई बार कहा है कि वे खुद को आम आदमी समझते हैं। यही सादगी उन्हें भीड़ से अलग बनाती है।

इंदौर की गलियों से निकलकर, रेडियो जॉकी की मामूली नौकरी से लेकर आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक बनने तक का सफ़र आसान नहीं था। लेकिन उनका संघर्ष उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से बड़े सपने देखते हैं।

भारत के लिए गौरव

न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी कॉमेडी शो करना केवल जाकिर की जीत नहीं, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक उपलब्धि है। इसने साबित कर दिया कि भाषा अब बाधा नहीं रही। हास्य, ईमानदारी और भावनाएं किसी भी भाषा में वैश्विक होती हैं।

आज जाकिर खान सिर्फ एक स्टैंड-अप कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक हैं। उन्होंने यह दिखाया है कि संघर्ष, मेहनत और अपनी जड़ों से जुड़े रहने से कोई भी शिखर छुआ जा सकता है।

इंदौर से न्यूयॉर्क तक का उनका सफ़र लाखों युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। करोड़ों की नेट वर्थ और अंतरराष्ट्रीय पहचान के बावजूद उनकी सबसे बड़ी पूंजी दर्शकों का प्यार है।

जाकिर खान ने यह साबित कर दिया कि सख़्त लौंडा सिर्फ एक मज़ाक नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, जज्बे और सपनों को सच करने का दूसरा नाम है।

अलसी परियोजना को मिला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार...

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीकेवी), रायपुर में संचालित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) अलसी को अलसी अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ एआईसीआरपी केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सीएआर द्वारा आयोजित अलसी एवं कुसुम की वार्षिक कार्यशाला, जो रांची में 9-10 सितंबर, 2025 आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान यह अवॉर्ड प्रदान किया गया। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और उन्होंने कहा कि यह सम्मान अलसी अनुसंधान को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने, नवाचार को बढ़ावा देने, एवं देश की कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु एआईसीआरपी अलसी टीम की सतत प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट कार्यशैली को दर्शाता है।

सम्मान समारोह में देश के प्रमुख आईसीएआर ऑथोरिटी एवं विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें डॉ. डी.के. यादव, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली; डॉ. संजीव गुप्ता, सहायक महानिदेशक (तिलहन एवं दलहन), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉ. आर.के. माथुर, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद तथा डॉ. एस.सी. दुबे, कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची शामिल थे। वहीं

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर स्थित एआईसीआरपी अलसी परियोजना की समर्पित टीम में प्रधान वैज्ञानिक डॉ. एन. मेहता, डॉ. संजय के. द्विवेदी, कौशल वैज्ञानिक डॉ.आशुलता, वैज्ञानिक डॉ. राजेश के.एक्का शामिल हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि को कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल के सक्षम नेतृत्व एवं अनुसंधान निदेशक डॉ. विवेक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में संभव बनाया गया।

क्या कोर्ट पहुंचने पर मिल जाएगा टोकन? जानिए लोक अदालत के नियम, वरना चालान नहीं होगा माफ...

ऑफिस पहुंचने की जल्दी हो या किसी इमरजेंसी की स्थिति में कई बार हम अनजाने में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर बैठते हैं। रेड लाइट पार करना, हेलमेट न पहनना या सीट बेल्ट लगाना भूल जाना जैसी छोटी-छोटी गलतियां अक्सर हमसे नजरअंदाज हो जाती हैं, लेकिन सड़क पर लगे हाई-टेक कैमरे इनसे चूकते नहीं है। इन कैमरों की निगरानी इतनी तेज और सटीक होती है कि जैसे ही कोई नियम टूटता है, चालान कटना लगभग तय होता है। ऐसे में बहुत से लोग चालान भरने की बजाय लोक अदालत का इंतजार करते हैं। आज देशभर में लोक अदालत लगने जा रही हैं, जिसमें हजारों वाहन मालिक अपने पेंडिंग चालान निपटाने की तैयारी में हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो ध्यान दें कि बिना टोकन के आप लोक अदालत में हिस्सा नहीं ले सकते हैं।

कहां मिलते हैं टोकन?- लोक अदालत के लिए टोकन ऑनलाइन बुक करते हैं। हालांकि आज के लिए टोकन मिलने बंद हो गए हैं। इसलिए अगर आपने टोकन बुक नहीं किया है, तो आप आज लगने जा रही लोक अदालत में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अब आपको अगली लोक अदालत का इंतजार करना होगा। बता दें कि अब अगली लोक अदालत 13 दिसंबर को लगेगी।

क्या-क्या दस्तावेज साथ ले जाएं?- अगर आपने टोकन लिया है तो लोक अदालत में जाते समय उसकी प्रिंट आउट कॉपी साथ जरूर रखें। यही एक दस्तावेज है जो आपके केस की पहचान करता है और कोर्ट में आपकी एंट्री सुनिश्चित करता है। इसके अलावा आमतौर पर किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वाहन से जुड़े मूल कागज़ात जैसे क्ष्ट और ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना समझदारी होगी।

समय का रखें खास ध्यान-लोक अदालत का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक तय किया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी समय पहुंच सकते हैं। आपको उसी स्लॉट में पहुंचना होगा जो आपके टोकन में दर्ज है। अगर आप लेट पहुंचे तो आपका केस नहीं लिया जाएगा और चालान माफ करवाने का मौका हाथ से निकल सकता है।

कौन-कौन से चालान निपटाए जा सकते हैं?- लोक अदालत में आमतौर पर माइनर ट्रैफिक उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग, क्ष्ट की कमी, रेड लाइट जंप करना जैसे मामलों को निपटाया जाता है। लेकिन ड्रंक ड्राइविंग, हिट एंड रन, नाबालिग द्वारा वाहन चलाना जैसे गंभीर मामलों को लोक अदालत में नहीं सुना जाता।

TATA ग्रुप की इस कंपनी का IPO अक्टूबर में आएगा! पैसे रखें तैयार, मिलेगा कमाई का शानदार मौका...

अगर यह आईपीओ सफल होता है, तो यह हुंडई मोटर इंडिया के अक्टूबर 2024 में आए 27,870 करोड़ के आईपीओ के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम होगा। टाटा ग्रुप की कंपनी, टाटा कैपिटल जल्द ही अपना बहुप्रतीक्षित 2 अरब डॉलर (लगभग 17,000 करोड़) का आईपीओ लॉन्च कर सकता है, जो अक्टूबर के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए दी गई 30 सितंबर की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, यह ढ्ढक्क्रह्र देश के वित्तीय क्षेत्र में सबसे बड़ा निर्गम बन सकता है। इसके जरिए, टाटा कैपिटल 18 अरब डॉलर (लगभग 1.5 लाख करोड़) के मूल्यांकन पर 2 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। यह मूल्यांकन अप्रैल 2025 में कंपनी के गोपनीय ढ्ढक्क्रह्र दस्तावेज़ दाखिल करने के समय के 11 अरब डॉलर के मूल्यांकन से काफी अधिक है।

आईपीओ में कुल 47.58 करोड़ शेयर शामिल होंगे

खबर के मुताबिक, अगर यह आईपीओ सफल होता है, तो यह हुंडई मोटर इंडिया के अक्टूबर 2024 में आए ?27,870 करोड़ के IPO के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम होगा। अगस्त में दाखिल किए गए अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के अनुसार, इस आईपीओ में कुल 47.58 करोड़ शेयर शामिल होंगे, जिसमें 21 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू होगा। इससे मिलने वाली रकम का उपयोग टियर-1 कैपिटल को मजबूत करने और कंपनी के लेंडिंग पोर्टफोलियो को बढ़ाने में किया जाएगा।

26.58 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) है। इसके तहत, प्रमोटर टाटा सन्स अपनी 23 करोड़ और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईएफसी) अपनी 3.58 करोड़ हिस्सेदारी बेचेगी। वर्तमान में, टाटा सन्स के पास 88.6% और आईएफसी के पास 1.8% हिस्सेदारी है।

RBI के नियमों के तहत लिस्टिंग अनिवार्य

यह आईपीओ आरबीआई के उस नियम के तहत लाया जा रहा है, जिसमें 'Upper Layer NBFCs' को तीन साल के भीतर शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना अनिवार्य है। टाटा कैपिटल को सितंबर 2022 में इसी श्रेणी में रखा गया था। टाटा कैपिटल ने हांगकांग, सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क और भारत में निवेशकों के साथ रोडशो आयोजित किए, जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन भी शानदार रहा है।

Q1 FY26 (अप्रैल-जून 2025) में कंपनी का शुद्ध लाभ दोगुना होकर 1,041 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ?472 करोड़ था। इस अवधि में कुल आय भी बढ़कर 7,692 करोड़ हो गई। हाल ही में हुए कुछ बड़े IPOs, जैसे HDB Financial Services (जून 2025 में 12,500 करोड़) और Bajaj Housing Finance (सितंबर 2024 में 135त्न प्रीमियम पर लिस्टिंग) की सफलता, निवेशकों के उत्साह को और बढ़ा रही है।

फेस्टिव सीजन में शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड और Buy Now Pay Later में से किससे होगा ज्यादा फायदा?

Festive Season Shopping: भारत में त्योहारों का सीजन गणेश चतुर्थी से शुरू होकर दिवाली, छठ, क्रिसमस और नव वर्ष तक चलता है। त्योहारी मौसम में खरीदारी, खाने-पीने और ट्रेवलिंग का खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में बहुत से क्रेडिट कार्ड, Buy Now Pay Later जैसे अन्य उपाय का इस्तेमाल करते हैं।

फेस्टिव सीजन के मौके पर कई जगह ऑफर्स और डिस्काउंट्स की भरमार शुरू हो जाती है। फ्लिपकार्ट और ऐमजॉन जैसे कई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फेस्टिव सीजन पर सेल शुरू कर देते हैं। इन सेल जहां सामानों पर डिस्काउंट का लाभ मिलेगा वहीं, दूसरी तरफ कई क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त ला की भी सुविधा मिलेगी। कई क्रेडिट कार्ड पर तो ग्राहकों को शानदार कैशबैक का लाभ मिल रहा है तो कहीं बाय नाउ पे लेटर (Buy Now Pay Later) की भी सुविधा मिल रही है। बाई नाऊ पे लेटर का आसान भाषा में मतलब होता है कि अभी खरीदें और बाद में भुगतान करें।

अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड बेहतर रहेगा या फिर Buy Now Pay Later की सुविधा ज्यादा बेहतर होती है। कई लोग सोच रहे हैं कि अगर वह बाई नाऊ पे लेटर का लाभ लेते हैं तो उनका क्रेडिट कार्ड की लिमिट ब्लॉक नहीं होगी। ऐसे में आइये जानते है कि इस फेस्टिव सीजन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना ठीक रहेगा या फिर बाय नाउ पे लेटर से?

जानिए बाय नाउ पे लेटर क्या है?

बाय नाउ, पे लेटर (BNPL) एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो खरीदारों को किसी वस्तु की कीमत एक साथ चुकाने की बजाय किस्तों में चुकाने की सुविधा देता है। आमतौर पर इसका उपयोग स्मार्टफोन, ब्रांडेड कपड़े या अन्य महंगे सामान की खरीदारी के लिए किया जाता है। अन्य लोन की तुलना में, BNPL लोन आमतौर पर ब्याज-मुक्त होते हैं। इनमें अतिरिक्त शुल्क भी कम होता है या नहीं होता है। हालांकि, इस तरह की सुविधा कई बार लोगों को डेट ट्रैप में फंसा सकती है।

बाय नाउ पे लेटर कैसे काम करता है?

'बाय नाउ पे लेटर' (BNPL) लोन की तरह काम करता है, जैसे कि पर्सनल लोन, कार लोन या होम लोन। इसमें जब आप कोई चीज खरीदते हैं, तो बेचने वाला यानी सेलर को पूरा पेमेंट पहले ही BNPL सेवा देने वाले कंपनी से मिल जाता है। इसके बाद, आप उस रकम को BNPL कंपनी को धीरे-धीरे किश्तों में चुकाते हैं। अक्सर इस प्रक्रिया में शुरुआत में 25% तक की डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। बाय नाउ पे लेटर में आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं और उसके बिल का भुगतान बाद में कर सकते हैं। इसमें शॉपिंग करने की क्रेडिट कार्ड की तरह कोई लिमिट नहीं रहती है। इसमें आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं और उसके बिल का भुगतान बाद में कर सकते हैं।

क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना

क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल आप छोटे लोन के जैसे कर सकते हैं। अन्य वित्तीय संस्थानों के द्वारा एक तय लिमिट दी जाती है जितना आप एक महीने में खर्च कर सकते हैं। पेमेंट के इस विकल्प में भी अभी खरीदने और बाद में भुगतान करने का लाभ दिया जाता है। सामान्यतौर पर अलग-अलग कंपनियों या बैंकों के द्वारा 45 से 50 दिन तक का ब्याज मुक्त भुगतान का लाभ मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड में आपको ईएमआई के ऑप्शन सेलेक्ट करने पर चार्ज भी देना होता है।

कौन सा ऑप्शन है बेस्ट

आप भी फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड पर आपको अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप बाई नाऊ पे लेटर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं।

'War 2' बनी बॉक्स ऑफिस का नया टाइगर, ऋतिक रोशन ने रच दिया एक्शन का नया इतिहास...

2019 में आई वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया था। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जबरदस्त केमिस्ट्री, हाई-ऑक्टेन एक्शन और सिद्धार्थ आनंद का टाइट निर्देशन फिल्म को एक मसालेदार थ्रिलर बना देता है। उसी सफलता के बाद वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में वॉर 2 की घोषणा हुई और इस बार निर्देशन की कमान अयान मुखर्जी ने संभाली, जिन्होंने पहले ब्रह्मास्त्र बनाई थी। उम्मीद थी कि इस बार कहानी और एक्शन का मेल एक और शानदार एंटरटेनर देगा। लेकिन अफसोस, फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। वॉर 2 की कहानी फिर से कबीर (ऋतिक रोशन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो जापान में एक मिशन पर है। लेकिन मिशन के बीच वही पुराना ट्विस्ट ङ्क एजेंट को गद्दार करार दिया जाना और फिर उसके देशभक्ति वाले इरादों का खुलासा। ये प्लॉट हम पहले टाइगर और पठान सीरीज़ में कई बार देख चुके हैं।

समस्या यह है कि कहानी बेहद सीधी और पुरानी लगती है। लगभग तीन घंटे की इस फिल्म में नयापन बिल्कुल नहीं है। मिशन, विश्वासघात, दुश्मनों का खेल और अंत में बड़ा खुलासा ङ्क सब कुछ पहले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अयान मुखर्जी का फोकस एक्शन पर इतना ज्यादा रहा कि उन्होंने कहानी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अयान मुखर्जी के लिए यह पहली एक्शन-थ्रिलर थी और साफ दिखता है कि वे इस जॉनर में सहज नहीं हैं। ब्रह्मास्त्र की तरह यहाँ भी उन्होंने स्केल बड़ा रखने की कोशिश की, लेकिन कंटेंट की कमी साफ झलकती है। फिल्म को 2 घंटे 53 मिनट तक खींचा गया है, जबकि कहानी आधे समय में भी खत्म की जा सकती थी।

एक्शन सीक्वेंसेज़ वाकई भव्य हैं, लेकिन लगातार एक्शन दिखाते जाने से दर्शक थक जाते हैं। कहानी और इमोशन के बिना सिर्फ एक्शन फीका और बेमतलब लगता है। कई जगहों पर फिल्म एक वीडियो गेम जैसी लगती है, जहाँ बस मारपीट और चेज़ सीन चलते रहते हैं।

ऋतिक रोशन- फिल्म में उनका काम औसत है। जब वे चुप रहते हैं तो स्क्रीन पर भारी लगते हैं, लेकिन कमजोर डायलॉग उनकी इंटेंसिटी को गिरा देते हैं। अयान मुखर्जी ऋतिक जैसे सितारे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए।

जूनियर एनटीआर- पैन-इंडिया अपील के लिए उन्हें फिल्म में जोड़ा गया, लेकिन उनका किरदार बेहद कमजोर लिखा गया है। उनका एंट्री सीन भव्य होने के बजाय मज़ाकिया लगता है। साउथ के सुपरस्टार को इस तरह वेस्ट करना सबसे बड़ी गलती है।

कियारा आडवाणी- उनका रोल बेहद छोटा और बेमकसद है। इसे कोई भी एक्ट्रेस निभा सकती थी।

अनिल कपूर और आशुतोष राणा- दोनों का काम ठीक-ठाक है, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था।

वरुण बडोला- एक सपोर्टिंग रोल में नज़र आते हैं, मगर उनकी मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता।

कुल मिलाकर एक्टिंग का स्तर औसत ही रहा। स्टारकास्ट जितनी बड़ी है, उतनी ही निराशाजनक परफॉर्मेंस निकलकर सामने आई।

फिल्म का बजट काफी बड़ा है और विजुअल्स व एक्शन सीक्वेंस इसकी झलक दिखाते हैं। सिनेमाटोग्राफी और लोकेशन्स शानदार हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज़ और शोरगुल वाला है, जो दर्शकों पर असर डालने के बजाय थका देता है। एडिटिंग कमजोर है ङ्क कई सीन्स बिना वजह लंबे खींचे गए हैं।

कमजोरियां

कहानी में नयेपन की पूरी तरह कमी।, ओवरडोज़ एक्शन- इमोशन और ड्रामा गायब। ,जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी जैसे कलाकारों का गलत इस्तेमाल। लगभग तीन घंटे लंबी फिल्म -दर्शक बोर हो जाते हैं।, डायलॉग्स बेहद कमजोर और असरहीन।

वॉर 2 वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होने के बावजूद निराश करती है। जहाँ पठान और टाइगर ज़िंदा है ने दर्शकों को बड़े पैमाने पर एंटरटेन किया, वहीं वॉर 2 में सब कुछ उल्टा हो गया। यह फिल्म बहुत लंबी, थकाऊ और बोरिंग है। न तो इसमें दमदार कहानी है, न शानदार निर्देशन और न ही कलाकारों का सही इस्तेमाल।

कहा जा सकता है कि खराब फिल्मों की लिस्ट में वॉर 2 ने टाइगर 3 को भी पीछे छोड़ दिया है। जो दर्शक ऋतिक रोशन या जूनियर एनटीआर के फैन हैं, उन्हें भी फिल्म निराश ही करेगी।

अगर आप सिर्फ हाई-ऑक्टेन एक्शन के शौकीन हैं और कहानी या लॉजिक की परवाह नहीं करते, तो शायद वॉर 2 आपको थोड़ी-बहुत पसंद आए। लेकिन यदि आप अच्छी स्क्रिप्ट और मनोरंजक फिल्म देखना चाहते हैं, तो यह मूवी निराश ही करेगी।

जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Save Water
करें वर्षा जल संरक्षित ज़रूर,
जल की कमी भी होगी दूर।
वर्षा जल
संरक्षित
घर
जल पुन: उपयोग
प्रणाली

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)

जनजातीय विकास का नया युग

₹375.71 करोड़ स्वीकृत 100 पुल + अन्य निर्माण कार्य

9 मंत्रालय

11 प्रमुख विकास गतिविधियां

18 जिले	**1442** गाँव	**2,306** बसाहटें	**56,669** परिवार

बचे 26 गांवों तक भी पहुंचेगी विकास की रोशनी

10,553 पक्के आवास पूर्ण	**500** किमी सड़कें पूर्ण	**44,101** आधार कार्ड जारी	**10,125** किसान क्रेडिट कार्ड जारी
1,04,743 आयुष्मान कार्ड बने	**36,521** जनधन खाते खुले	**46,024** जाति प्रमाण पत्र जारी	**228** गांवों में पाइप से जलापूर्ति
22,351 किसान सम्मान निधि पंजीकरण	**30,559** राशन कार्ड वितरित	**4,727** मातृत्व योजना लाभार्थी	

- **4 छात्रावास** व **आंगनबाड़ी केंद्रों** का निर्माणकार्य पूर्ण
- बड़ी संख्या में **मोबाइल टॉवरों** की स्थापना
- **7 वन धन विकास केंद्र** संचालित
- **8 बहुउद्देशीय केंद्रों** का निर्माणकार्य पूर्ण

विद्युतीकरण

7144 परिवार (ऑन ग्रिड)

729 परिवार (ऑफ ग्रिड)

मोबाइल मेडिकल यूनिट

57 यूनिट से **317 गांव** लाभान्वित

* यह आंकड़े माह जुलाई तक के हैं कार्य निरंतर जारी है

हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे

हमसे जुड़ने के लिए **QR स्कैन करें**

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ संवाद आर.ओ.-13431/167